हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

डाक पंजीकरण संख्याः एच.पी./42/एस.एम.एल. 2009 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

वर्ष 31 अंक 47 शिमला, 26 अगस्त–1 सितम्बर, 2009 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 3.00 रुपये वार्षिक 140 रुपये आजीवन 1500 रुपये website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

घर बैठे गिरिराज पाइये

गिरिराज का आजीवन ग्राहक बनने के लिए सदस्यता शुल्क 1500 **रुपये** बैंक ड्राफ्ट या मनिआर्डर के माध्यम से **निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, शिमला**–2 व वार्षिक सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क 140 **रुपये, सम्पादक, गिरिराज साप्ताहिक, शिमला**–171005 के नाम से भेजे।

पते में पिन कोड एवं दूरभाष या मोबाइल नं. लिखना न भूलें

इस अंक में

कृषि/बागवानी/विकास...	5
सर्व शिक्षा अभियान	6–7
साहित्य...	8
महिला/बाल जगत/स्वास्थ्य ...	9
पहाड़ी पृष्ठ	10

विज्ञापन प ष्ठ अतिरिक्त

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी के शिमला आगमन पर स्वागत करते हुए

प्रदेश में स्थापित होंगे सौर नगर

राज्य में ग़ैर परम्परागत ऊर्जा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नगरों को 'सौर नगर' घोषित करने की संभावना का पता लगाएगी।

यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के 65वीं जयन्ती पर हिम ऊर्जा द्वारा आयोजित सद्भावना दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेश की राजधानी शिमला के स्कूली बच्चों की 'अक्षय ऊर्जा रैली' को संबोधित करते हुए दी। मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह मामला केन्द्र सरकार के साथ उठायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ नगरों को 'सौर नगर' घोषित करने के प्रयास किए जाएंगे तथा इन नगरों में प्रकाश तथा ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ग़ैर परम्परागत ऊर्जा जलविद्युत क्षमता के संरक्षण एवं बचत में कारगर सिद्ध होगी, जिससे ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा

456 मेगावॉट कुल क्षमता की ऐसी 273 परियोजनाओं को निष्पादन के लिए प्रदेश के लोगों को सौंपा गया

किया जा सकेगा। प्रो. धूमल ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए ग़ैर परम्परागत ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि यह न केवल कम लागत वाली है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कारगर पहल की है। प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए समय- समय पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाता है। उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों में लोगों से सहयोग की भी अपील की, ताकि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से देश का आदर्श राज्य बन सके। मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 21 हजार मेगावॉट से अधिक की जलविद्युत क्षमता विद्यमान है तथा प्रदेश सरकार उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के दोहन के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2 मेगावॉट क्षमता तक की जलविद्युत परियोजनाओं को निष्पादन के लिए प्रदेश के उद्यमियों के लिए आरक्षित रखा गया है तथा हाल ही में 456 मेगावॉट कुल क्षमता की ऐसी 273 परियोजनाओं को निष्पादन के लिए प्रदेश के लोगों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि अधिक क्षमता की परियोजनाओं के आबंटन के समय प्रदेश तथा (शेष पृष्ठ 11 पर)

ग्राम सभा की विशेष बैठकें 6 सितम्बर को

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों शिमला में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों व प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की निजी भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए छः सितम्बर, 2009 को संपूर्ण प्रदेश में ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी ताकि और अधिक क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया जा सके।

रैगिंग निरोधक विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में बेहतर माहौल, वातावरण तथा अनुशासन कायम रखने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्था (रैगिंग का प्रतिषेध) विधेयक, 2009 को पारित किया। गौरतलब है कि वर्ष 1992 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आर्डिनेंस रैगिंग के विरोध में लाया था लेकिन सरकार के गिर जाने पर यह बिल का रूप नहीं ले सका। वर्तमान सरकार ने रैगिंग को रोकने के लिए 25 मार्च, 2009 को एक ऑडिनैंस लाया। इस एक्ट के तहत रैगिंग के दोषी छात्र को तीन वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये तक जुर्माना होगा। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले संस्थान में प्रमुख को भी दो वर्ष की कैद और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर संस्थान का प्रमुख आरोपी छात्र को निलंबित कर सकेगा। आरोप सिद्ध होने पर दोषी छात्र तीन वर्ष तक किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान

दोषी छात्र को तीन वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान

में प्रवेश नहीं ले सकेगा। इस विधेयक पर विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे ध्वनिमत से पास कर दिया। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस बिल के पारित होने के पीछे मूल भावना प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने की है ताकि वरिष्ठ छात्र भी अनुशासन में रहें। उन्होंने कहा कि कानून में रैगिंग पर रोक लगेगी। इस बिल को सभी पहलुओं पर विचार के उपरांत तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का मकसद उन छात्रों को रैगिंग के भय से मुक्त करना है जो इससे डरकर शिक्षण संस्थानों को छोड़ देते हैं। शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने सदन को बताया कि वर्तमान सरकार ने रैगिंग को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए तथा मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय,तकनीकी विश्वविद्यालय, बागबानी व कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं, के प्रमुखों को इस बाबत पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक स्तर इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए गहन विचार–विमर्श किया गया।

सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण गतिविधियों पर व्यय होंगे 1.83 करोड़

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, समेकित बाल विकास सेवाएं, किशोरी शक्ति योजना, बाल विकास समृद्धि योजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा कन्या भ्रूण हत्या के दुष्प्रभाव इत्यादि की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम, पर्यवेक्षक वृत्त परियोजना तथा जिला स्तर पर सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियों के आयोजन पर 1.83 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। श्रीमती चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम–2005, हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, दहेज प्रतिरोधक अधिनियम, अनैतिक व्यापार दमन (रोकथाम)–1956 तथा बाल विवाह अवरोधक अधिनियम–2006 इत्यादि के प्रति भी लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि (शेष पृष्ठ 11 पर)

प्रदेश को 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम' में शामिल करने का आग्रह

प्रदेश सरकार ने केन्द्र से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश को 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम' में शामिल किया जाए। वन मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने यह मामला गत दिनों विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित वन एवं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत की सभी प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हैं, बावजूद इसके हिमाचल को देश में राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में कभी शामिल नहीं किया गया।

वन मंत्री ने पर्यावरण अधोसंरचना के विकास के लिए 'कार्पस निधि' स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को हिमालय के बहुमूल्य पारिस्थितिकीय संतुलन तथा वन संपदा के संरक्षण के लिए हिमालयी राज्यों को वित्त पोषित करना चाहिए। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए धन आबंटन की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इन राज्यों के लिए 'ग्रीन अकाउंटिंग' प्रक्रिया सृजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इन राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग देना चाहिए।

श्री नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 'कार्बन न्यूट्रलिटी' प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक भागीदारी मूल्यांकन पर आधारित सार्थक प्रयास आरंभ किए हैं। (शेष पृष्ठ 11 पर)

हिमालय की गोद में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान

● विनोद भारद्वाज

पहाड़ों की रानी शिमला से 50 किलोमीटर की दूरी पर हिन्दोस्तान-तिब्बत मार्ग पर स्थित एक छोटा सा गांव शिलारू आजकल यहां से गुजरने वाले सभी राहगीरों व स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इस आकर्षण का कारण है–यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा हिमालय की गोद में देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पहला एस्ट्रोटर्फ वाला हॉकी मैदान।

खूबसूरत वादियों के बीच स्थित शिलारू में कृत्रिम घास की हरियाली सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शिलारू तथा इसके आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र देश भर में बढ़िया किस्म के सेब, नाशपाती, बंद गोभी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। शिलारू में आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व बीज आलू का उत्पादन किया जाता था तथा जहां यह संस्थान निर्मित किया गया है, वहां कभी आलू के बड़े-बड़े खेत थे।

शिलारू में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे आयोजित

समुद्रतल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलारू से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नारकण्डा की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है तथा यह यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना है। इस मैदान के बन जाने से हॉकी के खिलाड़ियों को ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसका लाभ भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को यूरोप के देशों में प्रतियोगिताएं खेलने के दौरान मिलेगा, क्योंकि यूरोप के देशों की जलवायु ठंडी तथा यहां के समान है। यह मैदान अब हॉकी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। साई के प्रभारी श्री जितेन्द्र वैद्य जो स्वयं बैडमिंटन के राष्ट्रीय कोच रहे हैं, ने बताया कि एस्ट्रोटर्फ को यहां हालैंड से (शेष पृष्ठ 11 पर)

निजी विश्वविद्यालयों में हिमाचलियों को 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में खुलने वाले सभी निजी विश्वविद्यालयों में हिमाचली छात्रों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रोस्टर के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

तीन नये विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित अलग-अलग विधेयक पारित होने से पूर्व प्रो. धूमल सदन में विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया व श्री राजेश धर्माणी द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश के स्तरीय विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि जहां भी ये विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं वहां स्थानीय विधायकों को गवर्निंग काउंसिल में बतौर सदस्य शामिल किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने बताया कि पूर्व सरकार द्वारा पारित विधेयक में हिमाचली छात्रों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। जबकि वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलने वाले प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के लिए अलग से विधेयक पारित करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों के खुलने से जहां प्रदेश के छात्र लाभान्वित होंगे वहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तीन नये विश्वविद्यालय हैं-शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट साईंस, मानव भारती तथा अरनी विश्वविद्यालय।

हि.प्र. उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.बी. मिश्रा राजभवन शिमला में राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव से भेंट के दौरान।

97 उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मानित

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने विधायक श्री गोबिन्द राम के प्रश्न के उत्तर में विधान सभा में जानकारी दी कि सरकार नौकरियों में खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण के तहत 41 खेल शामिल हैं तथा हाल ही में इसमें हुशु और कोर्फबॉल भी शामिल किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष स्वतन्त्रता दिवस पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले 97 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिसमें जिला मण्डी के 8, सिरमौर के 2, कुल्लू के एक, ऊना के एक, सोलन के चार, बिलासपुर के 17, शिमला के 28, हमीरपुर के 5 और कांगड़ा के 31 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें 9,37,950 रुपये के पुरस्कार प्रदान किये गये।

उन्होंने कहा कि तीन खिलाड़ियों जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया था, इनमें शूटिंग में श्री समरेश जंग को 73 हजार रुपये, सूबेदार विजय कुमार को 60 हजार रुपये तथा श्रीमती सोनिया राय को 5.55 लाख रुपये प्रदान किये गये। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के लिए 21 कोचों के पदों को भरने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो खिलाड़ी अन्य जगह खेल रहे हैं और प्रदेश में आने के इच्छुक हैं उन्हें राज्य में लाने के प्रयास किये जायेंगे। मुख्य मंत्री ने बताया कि तीन वर्षों के दौरान राज्य में 85 खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया तथा खेल कोटे के अधीन विभिन्न विभागों में 420 पद रिक्त हैं।

विधानसभा प्रश्नकाल

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रभावी ढंग से लागू

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों विधानसभा में एक वक्तव्य में कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को निर्मल हिमाचल बनाने के लिए कृतसंकल्प है तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को प्रदेश में प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए गत डेढ़ वर्ष में कई कदम उठाये गये हैं।

सरकार का यह प्रयत्न है कि इसे पूर्णतया समुदाय आधारित कार्यक्रम बनाया जाये। इस उद्देश्य से जहां एक ओर बड़े स्तर पर प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य किये जा रहे हैं वहीं सरकार ने सम्बन्धित संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायतों व महिला मण्डलों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर पुरस्कृत करने के लिए महर्षि वाल्मीकि स्वच्छता पुरस्कार तथा महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की है। वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रारम्भ किये जिसके अंतर्गत खण्ड, जिला, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम आने वाली पंचायतों को क्रमश: एक लाख, तीन लाख, 5 लाख एवं 10 लाख रुपये के पुरस्कार दिये गये।

गत वर्ष इस प्रतिस्पर्धा में लगभग 400 ग्राम पंचायतों ने भाग लिया जिनमें से 51 पंचायतों को खण्ड स्तरीय पुरस्कार, 12 पंचायतों को जिला स्तरीय और 7 पंचायतों को मण्डल स्तरीय एवं एक ग्राम पंचायत को राज्य स्तरीय पुरस्कार 15 अगस्त, 2008 को पांवटा में प्रदान किये गये। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में 900 ग्राम पंचायतों ने विभिन्न स्तर पर भाग लिया। पुरस्कार के चयन हेतु खण्ड, जिला, मण्डल, राज्य स्तरीय चयन समितियां गठित की गईं जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों से जाने माने व्यक्तियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया।

विभिन्न स्तर पर गठित इन अवलोकन समितियों ने इन सभी 900 ग्राम पंचायतों में जाकर निर्धारित पहलू नामत: व्यक्तिगत सफाई, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में स्वच्छता, जीवन निर्वाह की गुणवत्ता, ठोस एवं तरल कचरे का उचित प्रबन्ध एवं सम्पूर्ण स्वच्छता हेतु समुदाय की भागीदारी एवं संस्थागत योगदान के आधार पर निरीक्षण किया है।

एक करोड़ औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य

राज्य में इस वर्ष वन विभाग द्वारा एक करोड़ औषधीय पौधे लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 2.90 करोड़ अन्य पौधे भी इस वर्ष दिसम्बर तक रोपित करने का लक्ष्य है। यह जानकारी वन मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औषधीय पौधों का रोपण पहली बार हुआ है तथा इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को इस तरह के पौधों की खेती करने के लिए प्रेरित करना है। इससे लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जन-जन संजीवनी अभियान के तहत साढ़े बारह लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया था लेकिन योजना के तहत साढ़े पन्द्रह लाख पौधे लगाये गये। वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष वन विभाग की नर्सरियों में 2.90 करोड़ पौधें हैं तथा लोगों को 1 करोड़ औषधीय पौधे जो 2500 हेक्टेयर भूमि पर रोपे जायेंगे, वितरित करने के लिए सभी प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

नरेगा के तहत 4.20 करोड़ व्यय

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2008-09 में रामपुर ब्लॉक में नरेगा के तहत कुल 4.20 करोड़ रुपये खर्च किये गये। उन्होंने बताया कि रामपुर ब्लॉक और इस विधान सभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में नरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है।

हि.प्र. विद्युत शुल्क विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक 2009 को पारित कर दिया। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सदन को जानकारी दी कि इस विधेयक के पारित होने से किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैग के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए ही इसे पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रतिपूरक बिजली शुल्क लिया जाता था। अब प्रतिशतता के आधार पर शुल्क लिया जायेगा।

मामलों की स्वीकृति ऑनलाइन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 5 जून, 2009 से स्वीकृति प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। यह जानकारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र रवि ने मुख्य मंत्री की ओर से विधायक श्री राकेश पठानिया के प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि जून 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 121 आवेदन नई इकाइयों की स्थापना हेतु तथा 97 आवेदन इकाइयों को चलाने हेतु ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

औषधी उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति करेगी तथा सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी तैनात किये जायेंगे। ये अधिकारी लाइसेंस को निरस्त करने व अन्य कार्यों की देखरेख करेंगे। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुआयामी कदम उठाये जायेंगे तथा वर्तमान सरकार मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रही है।

यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव बिंदल ने विधान सभा में नियम 63 के तहत विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया तथा श्री सुरेन्द्र भारद्वाज द्वारा इस विषय पर लाई गई चर्चा के उत्तर में दी। इस चर्चा में 11 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्थिति से पूरी तरह से अवगत है तथा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में देश की लगभग 25 प्रतिशत आयुर्वेद तथा एलोपैथिक औषधियां निर्मित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य औषधीय उत्पादन के मामले में पूरे देश में नम्बर वन पर पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियामक गठित किया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2008 से जून 2009 तक 1289 दवाइयों के नमूने लिये गये तथा इनमें से 10 मामले मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाये गये तथा इनके खिलाफ मामले भी दर्ज किये गये।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री रमेश धवाला ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि गंदम, दाल व चावल के नमूने शिमला में जांचे जा रहे हैं तथा विभाग पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2008-09 के दौरान 42,52,313 रुपये का जुर्माना किया गया जबकि अप्रैल से जून 2009 तक 12,979 रुपये का जुर्माना दोषियों पर किया गया।

पब्बर पेयजल योजना पर व्यय होंगे 1198 करोड़

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र रवि ने विधान सभा में विधायक श्री रूप सिंह के प्रश्न के उत्तर में बताया कि शिमला शहर के लिए पब्बर नदी से एक ऐसी योजना का प्रयास किया जा रहा है जिससे आने वाले 30-40 वर्षों तक शहर में पानी की कमी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने शिमला शहर के लिए वर्ष 2042 तक को पेयजल जरुरतों को मद्देनजर रखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे केन्द्र सरकार ने वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को प्रेषित किया है। इस योजना पर 1197.60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि शिमला शहर के लिए पब्बर नदी से पानी जाबल गांव के नजदीक डियोढी, चिड़गाव, रोहडू, मैंदहली, पुजारली, कन्दया, धनासीधार, सुरंग द्वारा, मटली, हरयाला, रलाली, मेल नाला, रयोग तथा रैन घाटी होकर आयेगा।

उन्होंने बताया कि यह योजना प्रवाह योजना है तथा एक बार बन जाने पर इस पर कोई भी खर्च नहीं आयेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना को जवाहर लाल नवीकरण योजना के तहत लाकर विश्व बैंक को वित्त पोषण के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2042 में शिमला की आबादी 6,38,026 हो जायेगी तथा उस समय 101.92 एमएलडी पानी की आवश्यकता होगी जबकि अभी 54.54 एमएलडी पानी ही उपलब्ध है।

सिंचाई मंत्री ने विधायक श्री विपिन परमार के प्रश्न के उत्तर में बताया कि कृपाल चन्द कूहल जो न्यूगल से आरम्भ होती है को प्रदूषित करने वालों एवं अतिक्रमण करने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी।

विधायक श्री सुभाष मंगलेट के प्रश्न के उत्तर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नेरवा मण्डल में कुल 413 योजनाएं हैं और नेरवा उपमण्डल में 165 योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 तक 53 योजनाएं और बनकर तैयार हो जायेंगी।

सिंचाई मंत्री ने बताया कि राजगढ़ उपमण्डल में 2.49 करोड़ रुपये की शहरी पेयजल आपूर्ति योजना तथा नाबार्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर 76.22 लाख तथा एआईपी के तहत 3.64 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। यह जानकारी उन्होंने विधायक श्री गंगू राम के प्रश्न के उत्तर में दी।

मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान

पूर्व पार्षद संजीव शर्मा ने मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को 18 हजार रुपये मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए भेंट किए। मुख्य मंत्री ने संजीव शर्मा को राहत कोष के लिए राशि दान करने के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री राहत कोष में एकत्रित धनराशि का उपयोग समाज के कमजोर वर्ग तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है।

राज्य की अदालतों में वीडियो कांफ्रेंस सुविधा शीघ्र

- अदालतों में ढांचागत विकास के लिए 20 करोड़
- 6957 लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान
- तीन स्थायी लोक अदालतें गठित

हिमाचल प्रदेश की अदालतों एवं जेलों को वीडियो कांफ्रेंस सुविधा से जोड़ा जाएगा। राज्य के कानून मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने गत दिनों नई दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य न्यायधीशों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में अदालतों के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा प्रारम्भिक तौर पर जिला न्यायालय कुल्लू, धर्मशाला, शिमला एवं मण्डी को वीडियो कांफ्रेंस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्ट्रल जेल शिमला तथा मार्डन सैन्ट्रल जेल नाहन तथा जिला जेला धर्मशाला एवं बिलासपुर को भी शीघ्र ही वीडियो कांफ्रेंस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रयोग ई-मेल आधारित संचार व्यवस्था, सूचना का इलेक्ट्रानिक प्रवाह तथा अदालती कार्य में इंटरनेट के व्यापक उपयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी से उठाया है। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ अदालतों में ढांचागत विकास के लिए राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत नए अदालती परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों की संरचना की जाएगी।

श्री जे.पी. नड्डा ने बताया कि अदालतों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के दो नए पद सृजित किए गए हैं जिससे राज्य में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुकदमों के तत्काल निपटारे के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई है तथा जूनियर डिविजन स्तर के 13 नए सिविल जज कोर्ट स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुकदमों के समयबद्ध निपटारे के लिए उच्च न्यायालय मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर प्रगति का आंकलन कर रहा है। उन्होंने बताया कि लम्बित मुकदमों के निपटारे के लिए पिछले तीन सालों के दौरान 6 नए सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पदों का सृजन किया गया है जिससे राज्य में अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है।

उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य में न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई है तथा राज्य के न्यायिक अधिकारियों को गहन एवं अग्रिम प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल भी भेजा जा रहा है।

श्री नड्डा ने बताया कि राज्य में न्यायिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है जिसके अन्तर्गत गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत अब तक राज्य में 6957 को नि:शुल्क सहायता प्रदान की गई है जिसमें 2465 महिलाएं सम्मिलित हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की अदालतों में मुकदमों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान यंत्रावली को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों को निपटाने में प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है, जिन्होंने अब तक 108 मामलों का प्रभावी निपटारा किया है।

774 पेंशन के नए मामले स्वीकृत

हमीरपुर जिले में पिछली तिमाही के दौरान 774 पेंशन के नए मामले स्वीकृत किए गए। यह जानकारी उपायुक्त श्री अभिषेक जैन ने गत दिनों हमीरपुर में दी।

उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

निजी बस आपरेटरों से निर्धारित रूटों पर बस चलाने को सुनिश्चित बनाया जाएगा

परिवहन मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ने सदन में बताया कि सरकार उन निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो निर्धारित रूटों पर बसें नहीं चला रहे हैं या उन्होंने अपने रूटों को सबलेट किया हुआ है।

श्री महेन्द्र सिंह ने विधायक श्री दिलेराम व श्री गोबिंद राम द्वारा पूछे एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि वे यह सुनिश्चित बनाएंगे कि प्राइवेट बसें निर्धारित रूट पर ही चलें। उन्होंने बताया कि अगर निर्धारित रूट पर निजी ऑपरेटस द्वारा बस नहीं चलाई जाती, तो इस रूट पर राज्य पथ परिवहन की बसें निश्चित तौर पर चलाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि पहली जनवरी, 2009 से 15 जुलाई तक 288 बस रूट जारी किए गए हैं तथा अभी तक 2858 निजी बस रूट चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे निजी बस ऑपरेटरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो यात्रियों को सही सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तथा जहां सड़क का निर्माण हो गया है, वहां पर भी निजी बसों को चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगर ऐसे रूटों पर निजी ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे तो सरकार इन रूटों पर लोगों की सुविधा के लिए बसें चलाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार नए निजी बस रूट जारी करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि नए बस रूट जारी करने की संख्या तथा समय अवधि आवेदन पत्रों की संख्या तथा जनता की मांग पर निर्भर करती है जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

नारग विद्युत सब-स्टेशन पर होंगे पांच करोड़ व्यय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि नारग क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की लागत से विद्युत् सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इस सब स्टेशन से नारग क्षेत्र के सभी गांवों की बिजली की कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी।

डॉ. बिन्दल गत दिनों ज़िला सिरमौर के राजगढ़ उपमण्डल में सोलन ज़िला के साथ लगते घड़ासर में स्थानीय मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।

डॉ0 राजीव बिन्दल ने कहा कि ओच्छघाट से कालाघाट सम्पर्क सड़क को पक्का करने तथा नालियां बनाने पर 1.71 करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे। ज़िला की अर्थव्यवस्था कृषि तथा बागबानी पर निर्भर है। सरकार का प्रयास है कि 2011 तक 250 की आबादी वाले प्रत्येक गांव में सड़क पहुंचाई जाए, जिससे कृषक अपने उत्पादों को मण्डियों में ले जाकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में बे-मौसमी सब्जियों के उत्पादन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए महत्त्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान समृद्धि योजना आरम्भ की गई है जिसमें पाली हाऊस व पानी की छिड़काव सिंचाई योजना पर सरकार द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ज़िला में कृषि, पशुपालन, उद्यान तथा मत्स्य संबंधी योजनाओं के लिए इस वर्ष 17.70 लाख रुपये व्यय कर रही है। इससे कृषक खेतीबाड़ी के साथ-साथ उद्यान और मत्स्य पालन जैसे व्यवसायों से भी अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि घड़ासर की उठाऊ सिंचाई योजना पर 57 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे। इस योजना से यहां के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

कविता संग्रह 'दर्द-ए-दिल' का विमोचन

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी श्री खुशहाल शर्मा द्वारा लिखित कविता संग्रह 'दर्द-ए-दिल' का विमोचन किया। इस कविता संग्रह में लगभग 80 कविताएं संग्रहित की गई हैं। कवि ने इस संग्रह को प्रख्यात चित्रकार निकोलस रौरिक को समर्पित किया है। श्री खुशहाल शर्मा ने स्वयं रचित कविता संग्रह 'जाहन्वी' भी मुख्य मंत्री को भेंट किया। प्रो. धूमल ने श्री खुशहाल शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके प्रयास के लिए उन्हें बधाई दी।

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 'पर्यटक सुरक्षा बल' का गठन किया जाएगा

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्यटक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। राज्य की पर्यटन सचिव श्रीमती मनीषा नंदा ने गत दिनों नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि प्रस्तावित बल राज्य पुलिस तथा पर्यटकों के बीच एक कड़ी का काम करेगा तथा यह बल पर्यटकों की सुरक्षा, सहायता, सलाह के लिए समर्पित बल के रूप में गठित किया जाएगा।

श्रीमती मनीषा नन्दा ने कहा कि राज्य सरकार अमीर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्य में विद्यमान 57 हैलीपैडों के अधिकतम सदुपयोग के लिए हैलीटैक्सी सर्विस शुरू करने पर विचार कर रही है ताकि राज्य के पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने राज्य के मुख्य हैलीपैडों पर हैलीपोर्टस् स्थापित करने के लिए उदार केन्द्रीय मदद की मांग की। श्रीमती नंदा ने बताया कि राज्य में पर्यटन के ढांचागत विकास तथा पर्यटकों के निरन्तर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 20 वर्षीय पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

पर्यटन विकास तथा पर्यटकों के निरन्तर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 20 वर्षीय पर्यटन मास्टर प्लान तैयार होगा

उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने होम स्टे योजना को वैट से मुक्त किया है तथा होम स्टे परिसरों के बिजली एवं पानी के कनैक्शन घरेलू दरों पर प्रदान किये जा रहे हैं। श्रीमती नन्दा ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर पर्यटन ढांचागत विकास के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की निर्माण अवधि को बढ़ाने की मांग की तथा पहाड़ी राज्यों में लागत में बढ़ोतरी के मद्देनजर होटल प्रबन्धन संस्थान एवं फूड क्राफ्ट इन्स्टीच्यूट की वास्तविक निर्माण लागत राशि राज्य को प्रदान करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के दौरान राज्य में पर्यटकों की संख्या में 10 से 12 प्रतिशत के बीच में बढ़ोतरी दर्ज की गई तथा बताया कि वर्ष 2008 के दौरान राज्य में 4 लाख विदेशी पर्यटकों सहित कुल 18 लाख पर्यटकों ने राज्य का भ्रमण किया।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत् 25 करोड़ व्यय

सिरमौर जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत् वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में 1490 योजनाओं पर लगभग 25 करोड़ रुपये व्यय किए गए। यह जानकारी उपायुक्त श्री पदम सिंह चौहान ने गत दिनों नाहन में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत् चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दी।

उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2008-09 में नाहन विकास खण्ड में 184 योजनाओं पर 1.73 करोड़ रुपये, पांवटा साहिब विकास खण्ड में 285 योजनाओं पर 3.90 करोड़ रुपये, संगड़ाह विकास खण्ड में 111 योजनाओं पर 1.42 करोड़ रुपये, शिलाई विकास खण्ड में 58 योजनाओं पर 1.26 करोड़ रुपये, राजगढ़ विकास खण्ड में 76 योजनाओं पर 1.10 करोड़ रुपये तथा पच्छाद विकास खण्ड में 114 योजनाओं पर 1.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग संगड़ाह, शिलाई, राजगढ़ तथा नाहन मण्डलों में वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत् विभिन्न विकास योजनाओं पर 1.07 करोड़ रुपये, 9 लाख रुपये, 1.07 करोड़ रुपये तथा 7 लाख रुपये व्यय किए गए।

श्री पदम सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के तहत् विकास खण्ड नाहन में 119 योजनाओं पर 1.48 करोड़ रूपये, पांवटा साहिब विकास खण्ड में 193 योजनाओं पर 3.05 करोड़ रूपये, संगड़ाह विकास खण्ड में 65 योजनाओं पर 1.34 करोड़ रुपये, शिलाई विकास खण्ड में 73 योजनाओं पर 1.13 करोड़ रुपये, पच्छाद विकास खण्ड में 62 योजनाओं पर 1.02 करोड़ रुपये तथा राजगढ़ विकास खण्ड में 78 योजनाओं पर 1.18 करोड़ रुपये व्यय किए गए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के संगड़ाह, शिलाई, पांवटा तथा नाहन मण्डलों में वर्ष 2007-08 में इस योजना के तहत् विभिन्न विकास योजनाओं पर 1.28 करोड़ रुपये, 9 लाख, 77 लाख रुपये तथा 4.75 लाख रुपये व्यय किए गए। उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पांवटा साहिब मण्डल में 5 योजनाओं पर 3.56 करोड़ रुपये तथा नाहन मण्डल में एक योजना पर 1.10 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

पांगी उपमंडल में शिक्षा क्षेत्र के लिए 93.17 लाख रुपये

जनजातीय क्षेत्र पांगी उपमंडल में शिक्षा पर 93.17 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। यह जानकारी गत दिनों आवासीय आयुक्त पांगी डॉ. डी.आर. भारती ने किलाड़ में छात्रों की 22वीं खण्ड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ करते हुए दी। प्रतियोगिता में 11 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के 350 छात्रों ने भाग लिया। डॉ. भारती ने बच्चों के अभिभावकों एवं अध्यापकों से आह्वान किया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें, ताकि निकट भविष्य में वे बेहतर नागरिक बनकर प्रदेश व देश की सेवा में अहम भूमिका अदा कर सकें।

सतलुज जलविद्युत निगम के अधिकारी, मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को शिमला में 1500 मेगावाट की परियोजना में प्रदेश की हिस्सेदारी के बीस करोड़ रुपये का चेक भेंट करते हुए

एसजेवीएन द्वारा 20 करोड़ का अंतरिम लाभांश प्रदान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड ने 1500 मेगावाट क्षमता के नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन (एनजेएचपीएस) से लगातार बेहतरीन निष्पादन को देखते हुए वर्ष 2009-10 के लिए 80 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। हिमाचल सरकार को इसकी 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के मद्देनजर आनुपातिक आधार पर 20 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान गत दिनों मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री हेमंत कुमार शर्मा ने शिमला में भेंट की।

गिरिराज
हिमाचल की प्रगति और संस्कृति का दर्पण

अपने कर्तव्य पूरे करना ही सही मायनों में धर्म का पालन है।
-अज्ञात

स्वतन्त्रता दिवस के उपहार

स्वतन्त्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन स्मरण करवाता है उन करोड़ों देशभक्तों की जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। आजादी के 62 वर्षों में देश के साथ-साथ इस छोटे से प्रदेश ने विकास के अनेक मील पत्थर स्थापित किये हैं। इन वर्षों में हिमाचल ने विकास के नये आयाम स्थापित कर अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित बनाकर आर्थिक सम्पन्नता की ओर कदम बढ़ा रहा है। मुख्य मंत्री द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर स्वतन्त्रता सेनानियों, कर्मचारियों, श्रमिकों एवं अन्य वर्गों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं जो सरकार की प्रदेश के विकास एवं जन कल्याण के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। स्वतन्त्रता सेनानियों व इनकी विधवाओं व अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी, उन सभी देशभक्तों के प्रति सम्मान है, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया। राज्य की आर्थिकी कृषि-बागबानी पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी। गांवों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तो प्रदेश की खुशहाली स्वत: हो जायेगी। पं. दीन दयाल किसान-बागबान समृद्धि योजना के प्रथम चरण की सफलता तथा ग्रामीणों के इस ओर उत्साह को देखते हुए इस योजना के द्वितीय चरण को आरम्भ करने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। यह निर्णय अवश्य ही कृषि आर्थिकी को सम्बल प्रदान करेगा। बीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने से अब हरित गृह व खेत फसलों से लहलहायेंगे। आर्थिक मंदी के इस दौर में रोजगार के अवसर प्रदान करना समय की मांग है। वर्तमान सरकार सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका के मद्देनजर सरकार द्वारा मार्च 2009 तक आठ वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले अनुबंध व दिहाड़ीदारों को नियमित करने के फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह गृह रक्षकों, ग्राम पंचायतों के चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी व मंदिरों में कार्यरत दिहाड़ीदारों को सरकारी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के समक्ष दिहाड़ी व 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान करना, सरकार की श्रमिकों के कल्याण की वचनबद्धता को दोहराता है। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पंजाब की पद्धति पर नये वेतनमान व महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा से दो लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। यह सर्वविदित है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रदेश की तरक्की जहां सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों पर निर्भर करती है वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत नागरिकों द्वारा भी इसमें योगदान दिया जा रहा है। प्रदेश एवं जन सेवा में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित कर सरकार ने जहां इनका मनोबल बढ़ाया है वे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ये सभी हिमाचल का गौरव हैं। इस वर्ष का स्वतन्त्रता दिवस सही मायनों में सभी वर्गों के लिए तोहफों से कम नहीं रहा। सरकार की नई घोषणाओं ने सभी वर्गों के तीव्र सामाजिक उत्थान की कटिबद्धता को परिलक्षित किया है। बस जरूरत है हम सभी को और निष्ठा एवं समर्पण की भावना से कार्य करने की ताकि प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर सके।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भिक शिक्षा

जन राय

▸▸ क्रांति शील वर्मा

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने सदैव ही बच्चों को नई सोच विकसित करने तथा जीवन में ऊंचा सोचने के लिए प्रेरित किया है। उनके शब्दों में 'हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशागत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर परिवार द्वारा संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। फिर शिक्षक आपको जीवन की ऊंचाइयों से अवगत करवाते हैं।' जीवन में शिक्षा की महत्ता को भारतीयों ने सदियों पहले जान लिया था। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार बहुत अधिक राशि खर्च कर रही है। हाल ही में सभी बच्चों की निशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में 86वां संशोधन पारित किया गया है जो संसद में काफी समय से लम्बित था। लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार विधयेक पास किया। राज्य सभा द्वारा 20 जुलाई को इस बिल को पास किया गया था। इस विधयेक में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसे पास होने में 16 वर्ष लगे। राइट टू एजुकेशन बिल 2008 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के उत्थान के लिए काफी सराहनीय कदम भी उठाए जा रहे हैं ।

संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार सभी राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करें। 'अनिवार्य शिक्षा' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकारों को वे सभी कदम उठाने जरूरी हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और वे एक निश्चित समयावधि विद्यालयों में पूरी करें। संशोधन में 'निशुल्क शिक्षा' के बारे में कहा गया है कि पढ़ाई की एवज़ में लिये जाने वाले शुल्क के साथ-साथ उन सभी शुल्कों को जो कि स्कूल प्रशासन के द्वारा छात्रों से लिए जाते थे, को हटा दिया जाए। 'निशुल्क शिक्षा' के आधार को आगे बढ़ाते हुए इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें, तथा अन्य अध्ययन सामग्री निशुल्क प्रदान की जाए। इस विधेयक के तहत प्रत्येक माता-पिता/अभिभावक का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने की आयु पर स्कूल भेजें तथा प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें पढ़ायें।

संविधान के संशोधन की अनुपालना के लिए सरकार को दो स्तरों पर काम करने के लिए बाध्य किया गया है, एक तो सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करना और दूसरे वर्तमान शिक्षा के स्तर में गुणवता लाना। प्रारम्भिक स्तर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि शिक्षा में गुणवता लाने के लिए विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं हों, अच्छे भवन हों, अध्यापक पर्याप्त संख्या में हों और वे गुणकारी शिक्षा देने में सक्षम हों तथा अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हों। अध्यापकों के शैक्षणिक स्तर में लगातार सुधार लाने के लिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधानों की जानकारी दी जाए। नई विधियों के द्वारा छात्रों का समग्र मूल्यांकन किया जाए। छात्रों के शैक्षणिक स्तर की नियमित जांच हो और पाठशालाओं की देखरेख के लिए एक प्रभावशाली तंत्र को विकसित किया जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि समुदाय और उसके प्रतिनिधियों की विद्यालय के प्रबन्धन में एक प्रभावशाली भूमिका हो। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किये हैं।

शिक्षा के उत्थान के लिए वर्ष 2000 से पूरे देश मे सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश के लिए इस परियोजना में पांच अरब बत्तीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके तहत विद्यालयों में मूल भूत सुविधाएं जैसे कक्षा कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, चार दीवारी इत्यादि उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है । विद्यालयों के रखारखाव तथा विकासात्मक गतिविधियों के लिए विभिन्न अनुदान नकद राशि के रूप में प्रत्येक वर्ष दिए जा रहे हैं। इन अनुदानों से स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए तथा उनको नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए समय समय पर विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को आसानी से विषय वस्तु को समझा सकें इसके लिए प्रत्येक अध्यापक को सालाना 500 रुपये शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि का प्रयोग अध्यापक अपनी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में ग्रामीण शिक्षा समिति का गठन किया गया है।

मूलभूत सुविधाएं जुटाने से हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। अधिकतर विद्यालयों में आज कमरों, पीने के पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था है। पुराने भवनों की मुरम्मत आदि कराने से विद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ है जो कि एक सराहनीय कदम है। परन्तु विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बना कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना होता है और यदि विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा गुणवतापूर्ण न हो और विद्यालय के परिणाम अच्छे न हों तो अन्य सभी सुविधाओं का विद्यालय में होना कोई मायने नंहीं रखता ।

शिक्षा में गुणवता लाना प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2002 से अध्यापकों की कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नई नई तकनीकों और अनुसंधानों से अवगत कराने के लिए प्रत्येक अध्यापक को हर वर्ष 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इन प्रशिक्षण शिविरों पर अब तक एक बड़ी धनराशि खर्च हो चुकी है परन्तु अभी तक इनसे शिक्षा में गुणवता लाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। इस बात का प्रमाण राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणामों से बखूबी मिल जाता है। इसलिए इन शिविरों का मूल्यांकन किया जाना बेहद आवश्यक है। कुछ लोगों का मानना है कि इन शिविरों में भाग लेने से अध्यापक कई-कई दिन तक विद्यालय से बाहर रहते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सत्य है कि प्रशिक्षण किसी भी कार्यक्षेत्र में व्यक्ति की कुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वहीं पर यह भी जरूरी है कि अध्यापक अपना अधिक से अधिक समय विद्यालय में लगाएं ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग को प्रशिक्षणों से सम्बधित शिविरों को छुट्टियों के दौरान लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विद्यालयों मे छात्रों की पढ़ाई पर कोई विपरीत असर न पड़े। उन विद्यालयों के अध्यापकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए जिनका परिणाम औसत से नीचे रहता है।

आज सरकारी विद्यालयों में छात्रों की घटती संख्या एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है जिसके कारण कई विद्यालय बन्द होने के कगार पर हैं। छात्रों की घटती संख्या के कारणों पर अध्यापकों और आम जनता में मतभेद है। अध्यापक वर्ग जहां जनसंख्या दर में गिरावट को इसका कारण मानते हैं वहीं आम लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर में गिरावट को इसका कारण बताते है। पढ़ाई के स्तर में गिरावट के लिए अध्यापक वर्ग का मत है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान उन्हें बहुत बार ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिससे शिक्षा का कुछ भी लेना देना नहीं होता जैसे चुनाव तथा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों से सम्बधित कार्य इत्यादि । यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी अध्यापक को ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जिससे विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो। इसके बावजूद भी राज्य सरकारें अध्यापकों को ऐसे कार्यों में लगा रही हैं। शिक्षा के स्तर मे गिरावट के वास्तविक कारण चाहे कुछ भी हों, सच्चाई यही है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है और इसी कारण सरकार को कई विद्यालयों को बन्द करने का निर्णय लेना पड़ रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एव्म प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 32,000 विद्यालयों में एक भी छात्र नहीं है।

जहां तक सामुदायिक भागीदारी की बात है तो ग्रामीण शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण वे विद्यालय के प्रबन्धन में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। अधिकतर स्थानों पर उनसे सहयोग केवल बैंक से राशि निकालते समय लिया जाता है। कई स्थानों पर तो ग्रामीण शिक्षा समितियों के चुनाव कई वर्षों तक नहीं कराए जाते जबकि यह चुनाव प्रत्येक वर्ष होने अनिवार्य हैं। ग्रामीण शिक्षा समिति पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि ज्यादातर ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली अनुदान राशियों के बारे पूरी जानकारी भी नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का ज़िम्मा विद्यालय के अध्यापकों का होता है जो कि पूरी जानकारी समुदाय के प्रतिनिधियों को देना उचित नंहीं समझते। ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए समुचित व्यवस्था का न होना बहुत चिन्तनीय है क्योंकि जन सहयोग के बगैर कोई भी कार्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरुक करना इसलिए भी अधिक जरूरी है क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून 2008 जो कि अब संसद से पारित हो चुका है, के लागू हो जाने के बाद हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्धन समिति (School Management Committee) का निर्माण किया जाना है जो विद्यालय प्रबन्धन में एक प्रभावशाली भूमिका निभायेगी। इससे समुदाय के प्रतिनिधियों की जिम्मेवारियां और शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी।

जनता के सहयोग के बगैर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि जनता, अध्यापक वर्ग और सरकार के मध्य एक समन्वय स्थापित हो और समुदाय के लोगों को और उनके प्रतिनिधियों को जागरुक किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से काफी कुछ किया जा रहा है परन्तु प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही का न होना एक बहुत बड़ी खामी है । सरकार को चाहिए कि ऐसे अध्यापकों की जवाबदेही तय करे जो कि अपने कार्य का निर्वहन सही ढ़ंग से नंहीं कर रहे । विद्यालय का संचालन पंचायतों के अधीन लाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए ताकि विकेन्द्रीयकरण की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सके तथा शिक्षा के क्षेत्र में आम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तभी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की जाने वाली भारी धन राशि का सही उपयोग हो पाएगा और 'पढ़ो और आगे बढ़ो' के नारे को सार्थक बनाया जा सकेगा।

आज के संदर्भ में महान दार्शनिक जे. कृष्णामूर्ति के शब्द सार्थक हैं कि 'शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना, किन्हीं तथ्यों को कंठस्थ करना मात्र नहीं है, यह सीखना भी शिक्षा है कि अवलोकन कैसे किया जाये।' अनिवार्य शिक्षा बिल न केवल देश में एक नई क्रांति का सूत्रपत करेगा बल्कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना को सार्थक करेगा।

शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के मुख्य बिन्दू

स 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क एव्म अनिवार्य शिक्षा।
स जन्म प्रमाण पत्र का अभाव पाठशाला में प्रवेश के लिए बाधा नहीं।
स अक्षम बच्चों को भी निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
स प्रवेश के समय छात्र व अभिभावक के साक्षात्कार लेने की मनाही।
स निजी विद्यालयों मे 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित।
स संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस लेने की मनाही।
स प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को अनुतीर्ण करने अथवा पाठशाला से निष्कासित करने की मनाही।
स प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ।
स छात्र के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक।

मलाणा में आया नया सवेरा

● संजीव शर्मा

कुल्लू घाटी के मलाणा के 37 वर्षीय प्रधान दिलेराम तथा ऐसे अनेक निवासी अपना सारा दिन खेती-बाड़ी, हल-बैल की बात करते हैं और बाहर से आने वालों से औषधीय जड़ी-बूटियों के बाजार भाव के बारे में पूछते हैं। वैसे मलाणा में बहुत कुछ आज भी देवता के कहने पर होता है, पर यह किसी देव आदेश का हिस्सा नहीं है बल्कि यह बदलाव की बयार है जो मलाणा के हर गली-कूचे में बह रही है और इस बयार के साथ हर मलाणावासी अपनी उस खूबसूरत और भोली-भाली जिंदगी को बुला रहा है, जिसे अढ़ाई दशक पहले उन्होंने चांदी के चंद सिक्कों की चकाचौंध में आकर इस बारे सोचना छोड़ दिया था। गांव के 72 वर्षीय बुजुर्ग जवित्र राम को आज भी याद है कि 1984 के आसपास की बात है।

कुछ विदेशी यहां की प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के शोध के लिए आए और उन्होंने गांववासियों को नशे की प्रवृत्ति की ओर धकेल किया। उसके बाद हर साल यहां काला धंधा करने वाले विदेशियों की आवाजाही बढ़ती गई और कब उनका गांव चरस का गढ़ बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। जिस गांव को लोग विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और सहकार के तौर पर जानते थे, वह पूरी दुनिया में नशे का प्रतीक बन कर रह गया। यहां के निवासियों को इस नशे की खेती की प्रवृत्ति से दूर करने के लिए 2006 में पहली बार चरस के इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए नारकोटिक्स विभाग की 200 लोगों की टीम अधीक्षक ओ.पी. शर्मा की अगुआई में यहां पहुंची। पहले साल मात्र 50 बीघा से भांग की फसल नष्ट की जा सकी। सरकार के प्रयास सफल हुए तथा आज मलाणा में औषधीय खेती की बात हो रही है जो आर्थिक उत्थान का विकल्प बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि मलाणा को यह नया रूप देने में भी नारकोटिक्स विभाग के अधीक्षक ओ.पी. शर्मा पहल कर रहे हैं। मलाणा की जमीन पर सालम पंजा, मुश्कबाला, कालाजीरा और ममेरी की पौध रोपी जा रही है। यह जड़ी-बूटियां रोग निवारक हैं और मलाणा को दुनिया भर में नई पहचान देंगी।

मलाणा में इस समय 352 परिवार हैं और यहां की जनसंख्या 2000 के करीब है। इसमें से 190 परिवार अपने यहां औषधीय खेती के लिए राजी हो गए हैं। कुछ और परिवारों के भी मार्च तक जुड़ जाने की उम्मीद है लेकिन इन सभी के मन में इस परियोजना की सफलता को लेकर प्रश्न जरूर हैं।

मण्डी के बग्गी में कार्यरत गैर सरकारी संस्था की इस मामले में मदद ली जा रही है। हिम्पा के 30 लोगों का एक दल मलाणा का अध्ययन करने आया है। इस दल में वैज्ञानिक और उद्यमी दोनों शामिल थे। बाकायदा मलाणा की भूमि के अनुसार फसल लगाने की सलाह दी गई है और हिम्पा ने बाजार भाव पर मलाणा में ही तमाम उत्पाद खरीदने की हामी भर दी है। उधर इन्हीं नवरात्रों में मलाणा में मलाणा कूप्स के नाम से एक सहकारी सोसायटी का गठन किया गया है। यह सोसायटी दो स्तरीय होगी। इसमें सभी 352 परिवारों के दस स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। हर समूह से एक चुना हुआ प्रतिनिधि सोसायटी का सदस्य होगा। इसके अलावा जमलू देवता का कारदार और पुजारी भी इसका सदस्य होगा तथा गांव को आठों चुघों (वार्डों) से भी एक-एक सदस्य को इसमें लिया जाएगा। इस तरह 20 लोगों की यह सोसायटी देव परम्पराओं का भी निवर्हन करेगी और आधुनिक खेती का इंतजाम भी उसी पुराने तरीके से करेगी जिससे मलाणा में सभी काम अब तक होते आए हैं।

हालांकि मलाणा के लोग अब स्वयं ही जड़ी-बूटी उत्पादन के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन अब उनकी पहल को बाहरी प्रत्युत्तर भी मिल रहा है। ओ.पी. शर्मा और हिम्पा इस काम के लिए विभिन्न जगहों से धन की व्यवस्था में जुटे हैं। ओ. पी. के मुताबिक इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल होने में तीन साल लगेंगे और हमारा प्रयास है कि तब तक मलाणा के लोगों को कुछ भी व्यय न करना पड़े।

हिमाचल सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम भी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है। निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया है। यहां आयोजित एक शिविर में ऋण लेने के लिए 25 आवेदन आए हैं जिन्हें जल्द ही औपचारिकता पूरी करने के बाद लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। निगम मलाणा में भेड़-बकरी, घोड़ा पालन और छोटी-मोटी दुकान स्थापित करने के लिए मात्र छ: प्रतिशत पर एक लाख तक का ऋण दे रहा है। इसी तरह कृषि विकास बैंक जैविक सब्जियों की खेती के लिए ऋण देने को आगे आया है।

मलाणा में नशे के व्यापार के कारण आज से एक वर्ष पूर्व कोई भी रात नहीं बिताना चाहता था। सुबह आकर, शाम को ही यहां से सैलानी चले जाते थे। लेकिन अब मलाणा में आए बदलाव के कारण यहां शोधकर्ता, पर्यटक तथा साहसिक पर्यटन प्रेमी रात को भी रुकने लगे हैं। मलाणा से नशे का अंधेरा छंट गया है तथा अब नए सवेरे का उदय हुआ है जहां अब सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में मोबाइल पर यह धुनें बज रही हैं–**दु:ख भरे दिन बीते रहे भइया/ सुख भरे दिन आयो रे।**

गरीबों व जरूरतमंदों को मिल रहे कल्याण योजनाओं के लाभ

आत्म सम्मान के साथ जीवनयापन

निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस वर्ग के लोगों के कल्याणार्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनेक समाज कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं जिसमें विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पैंशन गरीब, वृद्ध, विधवा एवं अपंग व्यक्तियों के लिये वरदान सिद्ध हो रही है जिसे वर्तमान सरकार ने 130 रुपये की वृद्धि करके 330 रुपये मासिक किया गया है।

कांगड़ा जिला में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में 1404 पैंशन के नये मामले स्वीकृत किये गये हैं जिससे अब जिला में सामाजिक सुरक्षा पैंशन पाने वाले वृद्ध, विधवा एवं अपंग पात्र व्यक्तियों की संख्या 46698 हो गई है। जिन्हें प्रतिमास 330 रुपये पैंशन प्रदान करने पर जिला में 19.42 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है, जबकि जिला में चालू वित्त वर्ष में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर कुल 24 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान कांगड़ा जिला में विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों पर 22.70 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई, जिसमें अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत 17 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। इसी प्रकार गृह अनुदान कार्यक्रम के तहत जिला में 3.45 करोड़ रुपये की राशि व्यय करके 897 अनुसूचित जाति, 385 अन्य पिछड़ा वर्ग और 34 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को गृह निर्माण हेतू अनुदान प्रदान किया गया।

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के तहत गत वर्ष में 252 गरीब निर्धन परिवारों को बेटी के विवाह के लिए लगभग 28 लाख रुपये की राशि दी गई। इसी प्रकार मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 18 लाख रूपये की राशि व्यय करके 2037 गरीब असहाय महिलाओं व बच्चों को लाभान्वित किया गया, जबकि हरिजन बस्ती सुधार योजना के तहत 91 लाख रूपये की राशि व्यय करके 252 हरिजन बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। अन्तर्जातीय विवाह के तहत 48 दम्पत्तियों को पुरस्कार के रूप में 12 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 2009-10 में अनुवर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत 1726 पात्र व्यक्तियों, गृह अनुदान कार्यक्रम के तहत 956 निर्धन परिवारों, मदर टैरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 2037 असहाय महिलाओं, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के तहत 313 तथा 141 हरिजन वस्तियों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार द्वारा निर्धन परिवारों के बेरोज़गार युवाओं के लिये सहयोग योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत 60 हजार रुपये वार्षिक आय वाले शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु निजी क्षेत्र के टैक्सटाइल, पैकेजिंग एवं फार्मेसी में 30 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें सरकार द्वारा एक हजार रूपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त युवा उसी उद्योग अथवा किसी और उद्योग में भी नौकरी कर सकते हैं। सरकार की कल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों के जीवन में आत्मविश्वास की एक नई आशा की किरण पैदा हुई है तथा इस वर्ग के लोग वर्तमान में अपने आप को असहाय न मानकर आत्मसम्मान के साथ समाज में जीवनयापन कर रहे हैं।

–बी.आर. चौहान

कृषक मित्र

भूमि कटाव रोकने के लिए बहुमूल्य सुझाव

डॉ. बृज लाल लकारिया
डॉ. जे. सोमासुन्दरम
डॉ. रवि वन्जारी

वर्षा ऋतु में बहते जल के द्वारा धरती की ऊपरी सतह पर स्थित मूल्यवान मिट्टी बहकर या उड़कर चली जाती है जिससे भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है और यदि इस पर काबू न पाया जाये तो धीरे-धीरे वह भू-भाग कृषि के लिए अयोग्य भी हो जाता है। मृदाक्षरण के लिए मुख्यत: दो कारक जिम्मेदार हैं, वे हैं जल व वायु। इनमें से भी अधिकांश भू-क्षरण की समस्या जल द्वारा ही है। हमारे देश में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने जो आंकड़ें दिए हैं उनके अनुसार 329 मिलियन हैक्टेयर में से 149 मिलियन हैक्टेयर जमीन जल अपरदन की समस्या से प्रभावित है। इस प्रकार देश का लगभग 50 प्रतिशत भू-भाग भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है।

वास्तव में भूमि कटाव एक प्राकृतिक क्रिया है। वर्षों पहले जब अधिकांश क्षेत्र कृषि के अंतर्गत नहीं था उस समय भू-क्षरण की समस्या इतनी विकराल नहीं थी, क्योंकि हमारी मिट्टी के बनने की दर मिट्टी के कटाव की दर के समान थी। परन्तु जब भूमि पर कृषि कार्यों की वजह से मानव हस्तक्षेप बढ़ा तो उससे भूक्षरण की समस्या और अधिक बढ़ गई। इसके मुख्य कारण ये हैं:-

(क) वनों का विनाश-जंगलों की अंधाधुंध कटाई से, वन मृदाक्षरण की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं।

(ख) चरागाहों का विनाश व उनका अधिक उपयोग-यदि वन व चरागाह अच्छे हों तो मृदाक्षरण नहीं होता है। परन्तु उनके बहुपयोग व दुरुपयोग से धीरे-धीरे वनस्पति गायब होने लगती है और भूमि कटाव की समस्या बढ़ने लगती है।

(ग) गलत तरीके से खेती करना- जैसे

दोषपूर्ण जुताई-ढाल की दिशा में जुताई व फसलों की बुआई इत्यादि।

वर्षा ऋतु में खेत खाली छोड़ना-कुछ क्षेत्रों में बरसात के मौसम में खेत खाली रहते हैं तो वर्षा का पानी सीधे जमीन पर गिरता है और मिट्टी के कणों को अलग करके बहाकर ले जाता है।

अधिक ढलान पर खेती करना-खेती करने के लिए कम ढलान वाली जमीन ज्यादा उपयुक्त होती है। अधिक ढाल पर भूमि कटाव की समस्या अधिक होती है।

गलत खेती पद्धति-भूमि कटाव बढ़ाने वाली फसलों का प्रयोग, गलत फसल चक्र अपनाना, मिश्रित खेती व पट्टीदार खेती का अभाव इत्यादि।

अधिक वर्षा।

मिट्टी का प्रकार।

जल बहाव से भूमि कटाव- 1 से 6 प्रतिशत ढलान पर बहता हुआ पानी छोटी- छोटी नालियों का जाल सा बना देता है। ये नालियां जुताई के समय समाप्त हो जाती हैं।

मृदाक्षरण के लिए मुख्यत: दो कारक जिम्मेदार हैं, वे हैं जल व वायु। इनमें से भी अधिकांश मृदाक्षरण की समस्या जल द्वारा ही है। हमारे देश में विभिन्न कार्यकर्ताओं ने जो आंकड़ें दिए हैं उनके अनुसार 329 मिलियन हैक्टेयर में से 149 मिलियन हैक्टेयर जमीन जल कटाव की समस्या से प्रभावित है। इस प्रकार देश का लगभग 50 प्रतिशत भू-भाग भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है।

खड्ड द्वारा भूमि कटाव- बहता हुआ जल आगे चलकरएक बड़ी खड्ड का रूप धारण कर लेता है जो काफी गहरी व चौड़ी होती हैं और काफी बड़े क्षेत्र का पानी इसमें से बहता है। इन्हें भू परिष्करण क्रिया द्वारा समतल नहीं किया जा सकता है।

नदी नालों से भूमि कटाव-नाले व नदियाँ सदैव अपने किनारे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और उपजाऊ जमीन बहकर चली जाती है।

भूमि संरक्षण व वर्षा जल प्रबन्धन हेतु दो संरक्षण विधियां मुख्यत: अपनाई जाती हैं। कम ढलान वाले खेतों के लिए वानस्पतिक उपायों की सिफारिश की जाती है। ऐसी स्थितियों में जहां भौतिक एवं मौसमी कारणों से सस्यात्मक उपाय पर्याप्त न हों वहां यांत्रिक उपायों की सिफारिश की जाती है।

वानस्पतिक उपाय

समोच्य कृषि- साधारणतया हल्की जमीनों पर ढलान की दिशा में जुताई एवं बुआई की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं क्योंकि ऐसा करना आसान होता है। परन्तु इससे अधिक अपवाह एवं भू-क्षरण होता है तथा खेत में नमी का असंतुलित वितरण होता है। समोच्य कृषि पद्धति में ढाल के विपरीत जुताई-बुआई व निराई-गुड़ाई करते हैं। ऐसा करने से पौध ढलान के अनुरूप बहते हुए पानी की गति को कम कर देते हैं जिससे उसके साथ बहते हुए मिट्टी के कण बहने से रुक जाते हैं तथा अपवाह भी कम होता है।

पलवार-पलवार, फसल अवशिष्टों, कार्बनिक खाद तथा दूसरी बिछाली (पत्तियां व घास इत्यादि) को खेत में फैलाने को कहते हैं। यह वर्षा बूंदों की सघनता, अपवाह, मृदा हानि तथा वाष्पीकरण के प्रभाव को कम करती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पद्धति अपवाह व मृदा हानि को नियंत्रित करने में सहायक है। विभिन्न प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि अवशिष्ट पलवार द्वारा अपवाह व मृदा हानि को क्रमश: 66 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

वानस्पति अवरोध-कुल मिलाकर बंध, जल संरक्षण उपायों में से एक प्रभावी उपाय है, परन्तु इन पर लागत लगती है और इनका समय-समय पर रखरखाव आवश्यक है। बंधों के विकल्प के रूप में, समोच्य रेखा पर ढाल के दोनों ओर कम दूरी पर उगाई गई घास के स्थायी पट्टीयुक्त वानस्पतिक अवरोध भी समान रूप से प्रभावशाली पाये गये हैं। घास पुंजों को दो तीन पंक्तियों युक्त 1.0 मीटर चौड़ी घास की पट्टी अपवाह बहाव के विरूद्ध सघन एवं सुदृढ़ अवरोध की तरह कार्य कर सकती है। वानस्पतिक अवरोध अपेक्षाकृत सस्ते एवं किसानों के मित्र होते हैं। यह अपवाह की गति को धीमा करते हैं तथा अवरोधों के

(शेष पृष्ठ 9 पर)

कृपया
पृष्ठ 6 – 7
के लिए
सेंटरस्प्रेड देखें

समीक्षा

समाज में पनप रही बुराइयों का यथार्थ चित्रण 'प्यास'

मानव समाज में कहानी सुनने और कहने की बड़ी प्राचीन परम्परा रही है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक संवेदनशील प्रबुद्ध व्यक्ति तब अपने परिवेश में कुछ विशिष्ट घटना या गतिविधि देखता है तो अनुभूतियों की किसी न किसी विधा में व्यक्त करने को लालायित हो उठता है। उसकी यह व्यग्रता तभी शांत हो पाती है जब तक उसे किसी के सामने व्यक्त न कर दे या कागज पर न उतार ले। ऐसा ही परिवेश समर्पित कथाकार भानु प्रताप कुठियाला को सहज ही उपलब्ध हुआ है, जिसकी परिणति उनके सघप्रकाशित कहानी संग्रह 'प्यास' के रूप में हुई है। इस संग्रह में

● डॉ. हरि सिंह पाल

कुल पंद्रह कहानियां संग्रहित हैं, यह है–प्यास, वृन्दा, जिज्ञासा, प्रतिज्ञा, जिन्दगी, लाल हवेली, विश्वासघात, आत्म सम्मान, रिश्ता, दोषी कोन, दीवाली का उपहार, दोस्ती का बंधन, गुरु दक्षिणा, भाग्य और वाह री दुनिया। इनमें से अधिकांश कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित व आकाशवाणी से प्रसारित भी हो चुकी हैं।

इसके आमुख में सुपरिचित रचनाकार और स्तम्भ लेखक डॉ. श्यौराजसिंह बेचैन ने सही ही लिखा है–कहानियों की भाषा पाठकों के अनुकूल है। प्रसंगों में सार्थकता है। लेखक के सामाजिक सरोकार निम्न कमजोर और उपेक्षित पात्रों के प्रति स्पष्ट ही पक्षधरता के हैं।

इस संग्रह की पहली कहानी जिसके आधार पर इस कृति का नामकरण किया गया है वह है–प्यास। इसमें विषम परिस्थितियों की मारी एक प्रबुद्ध नारी गोमती उर्फ सलमा की व्यथा वर्णित है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले अपने देवर से संघर्ष करती है फिर घर ही छोड़कर भाग जाती है। फिर दिल्ली में ही दो गुंडों से लोहा लेती है जिसमें से एक की गोमती के हाथों हत्या हो जाती है। और इस अपराध में उसे उम्र कैद हो जाती है। वह जेल में सुधार कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेती है और जेल से रिहा होकर किसी गांव में एक मुसलिम परिवार में एक सलमा नाम से शरण लेती है। वह बस्ती की औरतों और बच्चों को पढ़ाती और सिलाई कढ़ाई भी सिखाती है और अंत में गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु का वरण करती है।

> **कथाकार कुठियाला जीवन अनुभवों के रचनाकार हैं जिनकी गहन दृष्टि छोटी-छोटी घटनाओं को विस्तृत आकार देते हुए बढ़ती हैं। इन कहानियों के प्रसंग इतने सुस्पष्ट हैं कि पाठकों को लग सकता है कि ये उनके अपने जीवन और परिवेश से ही सीधे सुसम्बद्ध हैं।**

इसी प्रकार वृन्दा कहानी में एक अदम्य साहस वाली नारी वृन्दा की जीवन संघर्ष का जीवन्त दर्पण है। साधनहीन परिवार की लड़की कड़े परिश्रम से पढ़ लिख कर सामाजिक रूढ़ियों का परिष्कार कर कलेक्टर बन जाती है। 'जिज्ञासा' कहानी की नाजिया और नेहा, 'प्रतिज्ञा' की सुमन, 'लाल हवेली' की लाजवन्ती, 'विश्वासघात' की सुमित्रा, 'आत्म सम्मान' की चम्बा, 'रिश्ता' की राधा, 'दीवाली का उपहार' की धन्नी, 'दोस्ती का बंधन' की कामनी, 'भाग्य' की प्रीतिकौर और 'वाह ही किस्मत' कहानी की दिव्य कुठियाला की कहानियों में केन्द्रिय पात्र हैं। कोई मां की भूमिका में हैं तो कोई प्रयेसी और पत्नी, पुत्री, बहन, भाभी आदि की भूमिका में। नारी इन कहानियों में पूर्णरूपेण सशक्त बनकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। कथाकार के अनुसार इन कहानियों के कुछ पात्र तो निकट परिवेश से सम्बद्ध हैं। इसीलिए इनकी भूमिकाओं के साथ साथ पूरा न्याय हुआ है। कथाकार कुठियाला की कहानियों में कथानक विस्तृत फलक लिए हुए है। उनके पात्रों में यद्यपि मानसिक संघर्ष कम ही नजर आता है किन्तु प्रकृति चित्रण, परिवेश चित्रण तथा पात्रों के रेखाचित्र इन कहानियों में यथोचित स्थान ले पाये हैं। इन कहानियों में घटनाएं चलचित्र की भांति तेजी से आती हैं और दृश्य परिवर्तित कर जाती हैं। प्रतिज्ञा कहानी में सुमन, रणक्षेत्र में शहीद पति के अभाव में सास और ननद का अत्याचार सहती है एक दिन उसे ससुराल का सहारा छोड़ देने पर विवश होना पड़ता है फिर अपने पति के किसी मित्र का आश्रय पाती है। बेटे को पढ़ा लिखा कर सेना में पहुंचा देती है। अंत में सास, और ननद अपनी गलती पर पश्चाताप करती हैं। इस प्रकार परिस्थितियां यंत्रवत बदली जाती हैं। अन्य कहानियों में भी यही शैली देखने को मिलती है जिससे चरित्र चित्रण का पक्ष सबल नहीं बन पाता।

इस संग्रह की कहानियों की भाषा नगरीय जीवन के अधिक निकट है। शहरी परिवेश में आजकल अंग्रेजी के शब्द बहुतायत में प्रयुक्त होने लगे हैं। कथाकार कुठियाला ने भी अंग्रेजी के शब्दों से कोई परहेज नहीं किया है। इससे भाषा में रवानगी ही आयी है। हिन्दी का पाठक भला इनसे कैसे वंचित रह सकता है। जिन्दगी कहानी को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। इस कहानी में रेन शेल्टर, ब्रेड, किचन, सैटल किया, मीटिंग रखी है, गीजर फ्रिज, टेबल, रिटायर, रिटायरमेंट, चैक, एकाउंट, अंकल, मम्मी, पापा, रेडीमेड कपड़े आदि शब्दों का बखूबी प्रयोग हुआ है।

कथाकार ने इस संग्रह की कहानियों के परिवेश में विविधता बनाए रखने में सफलता पाई है। जैसे प्यासा कहानी में जेल का परिवेश है, तो वृन्दा में संघर्षरत निर्धन परिवार की व्यथा है और जिज्ञासा में कश्मीर के आतंकवाद से पीड़ित मुस्लिम व्यक्ति की। लाल हवेली कहानी में एक दलित युवती और एक सामंत के विवाह का वर्णन है। विश्वासघात में दहेज रहित विवाह के साथ साथ सूबेदार महाजन के त्रास से मुक्ति को केन्द्र में रखा है। आत्म सम्मान कहानी में एक नखरैल मालकिन को रास्ते में लाने का उपक्रम किया गया है। दोष कौन में पुलिस की मनमानी और कम्पनी मालिक के कुकर्मों को स्पष्ट करते हुए अंत में सत्य की विजय को प्रतिपादित किया गया है। अंतिम कहानी वाह किस्मत में एक गरीब और अनाथ युवक अपने बलबूते पर पढ़लिख कर नौकरी ढूंढ लेता है। फैक्टरी के मालिक की पुत्री उससे विवाह करना चाहती है मगर पिता नहीं होने देना चाहता। इसके प्रेमी को जालसाजी में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया जाता है किन्तु भाग्य से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और कम्पनी में डायरेक्टर भी बना दिया जाता है। इस प्रकार लगभग सभी कहानियों में अंत सुखद ही रहता है।

इस संग्रह की कुछ कहानियां पाठक को अंतरमन से छू जाती है। सामाजिक जीवन की कटु सच्चाई चलचित्र की भांति प्रस्तुत हो जाती है। गुरु दक्षिणा ऐसी ही कहानी है। पाश्चात्य प्रभाव में आकर आधुनिक दम्पत्ति अने पिता की सम्पत्ति हड़प कर उन्हें दर-दर की ठोकर खाने पर विवश कर देते हैं। इस प्रकार इस संग्रह की सभी कहानियां किसी न किसी समस्या का समाधान लेकर समाप्त होती हैं। यद्यपि मानव जीवन इतना सरल और सहज नहीं रह गया है कि प्रत्येक समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही मिल जाये। इसीलिए आधुनिक कहानियों में समस्याओं का निरूपण अधिक है समाधान कम। चूंकि कथाकार कुठियाला हिन्दी कथा संसार अभी प्रवेश कर ही रहे हैं इसलिए इनसे एकदम यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि फैंटेसी और कल्पना जगत से बाहर निकलकर कटु यथार्थ में पदार्पण कर लें। इसमें अभी समय लगना स्वाभाविक है।

कथाकार कुठियाला जीवन अनुभवों के रचनाकार हैं जिनकी गहन दृष्टि छोटी-छोटी घटनाओं को विस्तृत आकार देते हुए बढ़ती हैं। इन कहानियों के प्रसंग इतने सुस्पष्ट हैं कि पाठकों को लग सकता है कि ये उनके अपने जीवन और परिवेश से ही सीधे सुसम्बद्ध हैं। इनके पात्र हमारे अपने ही बीच के जाने पहचाने व्यक्ति हैं जो हमारी की तरह दैनन्दिन समस्याओं से दो चार होते हैं। व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोशित होते हैं खोजते हैं और फिर अंत में समाधान भी निकाल लेते हैं। कहानियों में मानवीय संवेदनाएं आकार गृहण करती प्रतीत होती हैं। मानव जीवन की आशा-निराशा, ईर्ष्या- द्वेष परिवारिक तथा सामाजिक विघटन मानसिक अंतर्द्वन्द्व मानवीय मूल्यों में गिरावट महिला सशक्तिकरण आदि की पृष्ठभूमि कथा संग्रह की कहानियों में प्रकट हुआ है। कथाकार ने सामाजिक सुधार व वैचारिक रूप से समतावादी समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है तथा विकृत हो रही समाज में पनप रही बुराइयों का यथार्थ चित्रण करने के साथ-साथ उनके कारण होने वाले दुष्प्रभावों व कहानियों का सत्याघाटन भी किया है।

भानु प्रताप कुठियाला का यह पहला कहानी संग्रह है, कथा जगत में एक समर्पित कथाकार के रूप में प्रविष्ठ हुए हैं। आशा की जा सकती है कि भविष्य में एक सफल कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। उनके कथाशिल्प में गहनता और मार्मिकता का पक्ष और सशक्त होगा। पहले ही कहानी संग्रह प्यासा के माध्यम से कुठियाला ने हिमाचल के कथाकारों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। एक सफल कथाकार के रूप में हिन्दी कथा जगत में प्रतिष्ठित होंगे। शुभकामनाओं के साथ।

सन्दर्भ- प्यास (कहानी संग्रह)
प्रकाशक-नवभारत प्रकाशन, डी-626, गली नं. 1, अशोक नगर शाहदरा दिल्ली-93.

क्या आप जानते हैं?

भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी

देश में ही परमाणु पनडुब्बी विकसित करने वाला भारत, विश्व का छठा देश बन गया है। 'आईएनएस अरिहंत' नामक इस परमाणु पनडुब्बी का जलावतरण 26 जुलाई, 2009 को विशाखापत्तनम में किया गया। ईंधन के लिए इसमें लगे परमाणु रिएक्टर का विकास बीएआरसी (BARC) में किया गया है और इसकी क्षमता 80 मेगावाट की है। एक बार इसमें संवर्द्धित यूरेनियम भरने के बाद महीनों ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। यह डीजल-इलैक्ट्रिक पनडुब्बियों से भिन्न है, क्योंकि इन पनडुब्बियों को ईंधन के लिए ऑक्सीजन लेने हेतु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए सतह तक आना होता है। जबकि परमाणु पनडुब्बी समुद्र में एक बार गोता लगाने के बाद छह माह से अधिक समय तक पानी के भीतर ही रहकर अपने कार्यों का संचालन कर सकती है। इसकी लम्बाई 112 मीटर है और इसमें 95 नौसैनिक तैनात रहेंगे। यह तारपीडो और बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित रहेगी। इसका भार 6000 टन है और इसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है।

1. रेलवे लाइन के लिए वह कौन सी सुरंग बनाई जा रही है जो भारत में सबसे अधिक लम्बी होगी?
2. भारत सरकार द्वारा गठित वह प्राधिकरण जो सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा?
3. भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था?
4. भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है?
5. मुक्त बाजार क्षेत्र (Free trade zone) घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है?
6. इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
7. शांति निकेतन की स्थापना किसने की?
8. भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे?
9. कठ उपनिषद् किस वेद से सम्बन्धित है?
10. हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है?
11. साहित्य अकादमी नई दिल्ली से कौनसी पत्रिका निकलती है?
12. किस रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरीटेज साइट बनाया गया है?
13. 'सोनापानी' ग्लेशियर किस जिले में है?
14. आंधा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है?
15. चम्बा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजियार की ऊंचाई कितनी है?

प्रस्तुति-नर्वदा कंवर

□□□

उत्तर-1. पीर पंजाल टनल (जम्मू-कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड परियोजना के मार्ग में यह ग्यारह किलोमीटर लम्बी टनल बनाई जा रही है इसके 2011 तक कार्यशील हो जाने की आशा है), 2. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 3. 1953 में, 4. संयुक्त राज्य अमरीका के साथ, 5. सांताक्रुज, 6. लाला लाजपत राय, 7. रवीन्द्रनाथ टैगोर, 8. पुर्तगाली, 9. यजुर्वेद से, 10. सत्यमेव जयते, 11. समकालीन भारतीय साहित्य, 12. कालका-शिमला रेल लाइन, 13. लाहौल स्पीति, 14. शिमला जिला में, 15. 1890 मीटर।

कविता — नई कलम

मानव

पेड़ काटते रहे
पहाड़ों को खोदते रहे
धूल उड़ती रही
वातावरण में प्रदूषण फैलता रहा
लेकिन मानव नहीं सुधर रहा है।
सूख गए हैं नदी नाले
मेघों ने बरसना छोड़ दिया
दूर हो रही है हरियाली
जीव जन्तु तरस रहे हैं
पानी की एक बूंद को
लेकिन मानव नहीं सुधर रहा है।

कहां गई वो हरियाली,
फसलों से लहलहाते खेत,
कहां गई वो पहाड़ियों को
ढकने वाली बर्फ की सफेद चादर
वो मन को छूने वाले झर-झर करते झरने
नदी नाले तालाब
सब नष्ट होता जा रहा है
लेकिन मानव नहीं सुधर रहा है।

जिस चोटी पर लगते थे
देवदार चील आदि के पेड़
उस चोटी पर लग रहे हैं टावर
जिसके खतरे में झूल रहा है
पशु पक्षी हर जीव जन्तु
लेकिन मानव नहीं सुधर रहा है।

एक दिन ऐसा आयेगा
अपने ही हाथों से खो देंगे सब कुछ
फिर न कुछ करने को रहेगा
और न कुछ कर पायेंगे
क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा
मानव क्यों नहीं सुधर रहा है।

▶▶ सुन्दर सिंह कौंडल

कहानी

आशीर्वाद

...मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले गये थे। बाद में तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि तुम घर से भी लापता हो तो मुझे बड़ी निराशा हुई थी।

● ओम प्रकाश शर्मा

गत सर्दियों की छुट्टियों में मैं शिमला आया हुआ था। ग्यारह बज चुके थे, सोचा क्यों न माल रोड़ का एक चक्कर ही लगा लिया जाये। घर से बाहर अभी कदम देने ही जा रहा था कि पीछे से पत्नी का आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, 'आज बाजार जा ही तो रहे हैं यह थैला भी साथ लेते जाइये। वापसी पर सब्जी मण्डी से ताजा साग भाजी भी लेते आइएगा।' पत्नी का कहना हुक्म चलाने से कम नहीं होता उसको मात्र कहने के रूप में न लेकर आदेश के रूप में लेना पड़ता है। छोटा शिमला से बैनमोर, शिमला क्लब होते हुए मैं माल रोड़ पर पहुंच गया। दिन के समय माल रोड़ पर अधिक सैलानी ही दिखाई देते हैं या अपनी अपनी दुकानों के सामने खड़े दुकानदार ग्राहक के इंतजार में धूप का आनन्द लेते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में माल पर अकेले घूमने का कोई आनन्द ही नहीं। हां, यदि मित्रों की टोली मिल जाये तो व्यक्ति स्कैंडल प्वाइंट पर खड़े-खड़े घंटों व्यतीत कर सकता है।

माल पर थोड़ी चहल कदमी की पर उस दिन कोई अंतरंग मित्र न मिला इसलिए मैं रीडिंग रूम में जा कर बैठ गया। दो चार समाचार पत्रों की सुर्खियां पढ़ लेने बाद मैं फिर नीचे उतर गयां पहले सोचा कि कॉफी हाउस में जाकर एक प्याला कॉफी का आनन्द लिया जाये पर अकेले कॉफी हाउस में बैठने की बात भी कुछ जंची नहीं। मैं सीढ़ियां उतर कर सीधा लोअर बाजार की ओर चल पड़ा। लोअर बाजार में कुछ सामान खरीदने के बाद मैं सब्जी मण्डी पहुंचा। थोड़ा-थोड़ा खरीदते हुए दो बैग भर गये थे। अब पैदल चलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं धीरे-धीरे घोड़ा अस्पताल के बस स्टॉप के लिए थाना सदर के पास से नीचे उतर गया।

छोटा शिमला की ओर जाने वाली बसें बस स्टैण्ड से भर कर आ रही थी। उनमें पैर धरने के लिए भी जगह नहीं थी। मेरे दोनों हाथों में सब्जी के थैले थे। मैं बस स्टैण्ड की ओर जाने का मन बना ही रहा था ताकि वहां से बस में बैठकर आया जाये। तभी अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी तथा चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति ने मुझे उसमें बैठने के लिए इशारा किया। मैंने पहले कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कि क्योंकि उन दिनों किडनी रैकेट की चर्चा बड़े जोरों पर थी। परन्तु पुन: जब कार के अंदर से व्यक्ति ने कहा, 'आप आ जाइए।' तो मैंने प्रश्न किया, 'आप कहा जा रहे हो?' उसके उत्तर में उसी व्यक्ति ने कहा, 'गुरुजी, आप भीतर आइए तो सही, आप जहां कहेंगे हम आपको वहीं छोड़ देंगे।'

मैंने गाड़ी का नम्बर देखा हिमाचल का ही था तथा साथ ही लिखा था हिमाचल प्रदेश सरकार। मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ। पहले दोनों थैले अंदर रखे और फिर कार में बैठ गया। कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोग बैठे थे। चालक ने अभिवादन किया तत्पश्चात वह मेरे परिवार का हाल पूछने लगा। मुझे लग रहा था कि यह युवक कोई जाना पहचाना है। मैं बार-बार अपने मस्तिष्क पर जोर डाल रहा था पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। गाड़ी सेंट एडवर्ड स्कूल के पास पहुंच गई थी। मैं अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और पूछ ही बैठा, 'आपकी आवाज तो जानी पहचानी लगती है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं पर आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि मेरा और आपका परिचय तो पुराना है पर हम कहां मिले, कब मिले यह कुछ भी याद नहीं आ रहा।'

'आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे मैंने भी आपको एक अरसे के बाद देखा है। कई वर्षों तक तो मैं भी शिमला से बाहर ही रहा। जब तो मैं आपके पास आया करता था। उस समय तो मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी।'

'आपका नाम?'

'गुलशन।'

'अरे तुम वहीं गुलशन तो नहीं हो जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर से चले गये थे।'

'हां, गुरुजी मैं वही गुलशन हूं।'

'तुमने आज मेरे लिए गाड़ी कैसे रोक दी? तुम्हारे प्रति मेरा व्यवहार तो कुछ ठीक नहीं था।'

'आप यह क्या कहते हैं? आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी ही बदौलत हूं। आपकी वजह से ही मैं अपना परिवार इज्जत से पाल रहा हूं।'

'मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले गये थे। बाद में तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि तुम घर से भी लापता हो तो मुझे बड़ी निराशा हुई थी।'

'उन दिनों मेरा पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। उस दिन जब आपने मेरी गलत हरकत पर मेरे मुंह पर चांटा रसीद किया था वहीं मेरे लिए आपका आशीर्वाद सिद्ध हुआ है। उस समय सभी छात्रों को सम्बोधित करते हुए आपने यह भी कहा था कि यदि हमारा पढ़ाई में मन न लगे तो हम लोगों को अपनी रुचि का कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अपने माता-पिता के खून पसीने की कमाई को इस प्रकार बर्बाद करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके की प्रेरणा मुझे तब तक किसी से नहीं मिली थी। पढ़ना मैं चाहता नहीं था इसलिए मैं घर से अपने कुछ कपड़े लेकर भाग गया।'

'भागकर तुम गये कहां? तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारी बहुत तलाश की थी परन्तु तुम्हारा तो कहीं भी कोई पता नहीं चला था।'

'मैं रेलगाड़ी से कालका पहुंचा। वहां पर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया और उसके साथ मैं अम्बाला चला गया। उसकी मदद से ही मैं अम्बाला की एक कम्पनी के ट्रक पर कंडक्टर लग गया।'

'फिर आगे क्या हुआ?' मेरे भीतर उसके बीते कल को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई थी।

'मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं ड्राईवर बनूंगा। ट्रक का उस्ताद बाहर से बड़ा कठोर लगता था पर था मन का साफ। काम के समय वह पूरी सख्ती से पेश आता था पर आगे पीछे वह मेरा बड़ा ध्यान रखता था। मेरे शौक को देखकर उसने मुझे गाड़ी से सम्बन्धित एक एक बात बतानी शुरू कर दी और ज्यादा क्या कहूं, एक साल के अंदर ही मुझे चालक के सारे गुर सिखला दिये। अब उस्ताद जी पीछे बैठे या लेटे रहते थे और मैं गाड़ी चलाता रहता था। मालिक को कहकर उन्होंने मेरा लाइसैंस भी बनवा दिया ओर कुछ महीने बाद मुझे अलग गाड़ी पर लगवा दिया।'

'क्या तुम्हें कभी अपने माता-पिता की याद नहीं आती थी?'

'क्यों नहीं, याद तो हरदम सताती रहती थी। पर मैं अपने पांवों पर खड़ा होकर ही घर आना चाहता था। हमारी कम्पनी की गाड़ी मैदानी इलाकों में ही चलती थी। इस कारण मैं शिमला नहीं आया। एक दिन किसी जान पहचान के व्यक्ति से पिता को मेरा पता लग गया और वे मुझसे मिलने अम्बाला आये। वे मुझे अपने साथ शिमला लाना चाहते थे परन्तु मेरे मना करने तथा मालिक के साथ कुछ बात करने के बाद उन्होंने मुझे विवश नहीं किया। मैं पहली बार खुद गाड़ी में सामान लेकर शिमला आया था। उस समय घरवालों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा था। उसके बाद आने का सिलसिला लगभग जारी रहा।'

'आजकल तुम्हारी रिहायश कहां है?'

'मैंने अम्बाला में जो पैसे जमा किये थे उससे मैंने यहां एक प्लाट ले लिया था। जिस पर हमने मकान बनवा लिया है। पर आजकल रात दिन कभी भी डियूटी पर हाजिर होना पड़ता है इसलिए सरकारी मकान मिला है। वहीं पर अपने परिवार के साथ रहता हूं।'

'तुमने तो काफी मेहनत कर अपने जीवन को संवारा है।'

'मैंने कुछ नहीं किया वह तो थप्पड़ के रूप में मिला आपका आशीर्वाद व आपकी प्रेरणा है जिसने मेरे जीवन को सही दिशा प्रदान की। मैं तो यह मानता हूं, गुरु के मन से निकले बुरे वचन भी अपने शिष्यों का सदा कल्याण ही करते हैं। मेरे कई साथी अभी तक पहले की तरह भटक रहे हैं उन्हें अभी तक कोई दिशा नहीं मिली। मैं तो एक बाबू के मुकाबले वेतन पाता हूं जो अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं वे अलग।'

इतने में हम छोटा शिमला पहुंच चुके थे। मैंने उससे गाड़ी रोकने को कहा। उसने कार को किनारे पर खड़ा किया। पहले तो वह मुझसे उसके घर चलने का आग्रह करने लगा परन्तु जब मैंने उसे अपनी विवशता बताई तो उसने स्वयं उतर कर मेरा दरवाजा खोला। मेरा समान पकड़कर मुझे नीचे उतरने में मदद की। उसने मेरा पता और दूरभाष नम्बर नोट किया। फिर झुककर मुझे प्रणाम किया और गाड़ी को स्टार्ट कर चल पड़ा। उस समय मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही थी। मेरी आंखें डबडबा आईं और तब तक कार को देखता रहा जब वह आंखों से ओझल नहीं हो गई।

कविता

वर्षा रानी

वर्षा रानी ऐ वर्षा रानी,
बड़ी अजब ये तेरी कहानी।
जब तू नीर न बरसाये,
किसानों को जीभर कर रूलाये।।
सभी लोग नीर को तरसे,
जब भी तू न बरसे।
हरे हरे खेत रह जाते सूखे,
दृश्य होते हर तरफ रूखे।
अब जा के तू जम के बरसी,
हर जिन्दगी अब धूप को तरसी।
हुये मार्ग अवरूद्ध चहुं ओर,
बादल छाये अब भी घनघोर।
मकान डूब रहे डंगे भी गिरते,
बिन छत लोग लाचार हो फिरते।
चारों ओर हो चुका पानी पानी,
अब बस भी कर तू वर्षा रानी।

सुरेन्द्र मिन्हास

(पृष्ठ पांच का शेष)

भूमि कटाव रोकने के लिए...

पीछे की ओर से अपवाद के जमाव को सुनिश्चित करते हैं। अवरोधों के लिए आर्थिक दृष्टि से उत्तम तथा सघन एवं बारहमासी आवरण प्रदान करने वाली घासों का चलन किया जाना चाहिए।

यांत्रिक उपाय

भूमि समतलीकरण-इससे पानी भूमि की सतह से कम बहेगा और मिट्टी के अंदर अधिक प्रवेश करता है और सिंचाई करने से आसानी रहती है। परन्तु समतलीकरण में भी थोड़ी सी ढाल अवश्य रखनी चाहिए अन्यथा खासकर भारी मृदाओं में खरीफ के मौसम में धान के अलावा दूसरी फसल उगाने में कठिनाई होगी।

समोच्य एवं श्रेणीबद्ध मेढ़ाबंदी-कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां ढाल 1 से 6 प्रतिशत तक रहती है। वहां पर ढाल के विपरीत सम्मोच रेखा पर मिट्टी का बांध (1.5 मीटर के कम ऊंचे) बनाना चाहिए। अत: अपवाह को रोककर मिट्टी में प्रवेश करने का अवसर दिया जाता है। इस बांधों पर घास लगाना चाहिए जिससे वे जल्दी न टूट जायें। यदि वर्षा अधिक होती हो (800 मिलीमीटर से अधिक) और मृदा में पानी जाने की दर कम हो तो श्रेणी बांध बनाने चाहिए। ये सभी सम्मोच बंध की तरह ही ढाल के विपरीत बनाये जाते हैं परन्तु बंध द्वारा रोक गये अधिक पानी के सुरक्षित निस्सरण हेतु बंध 1 से 2 प्रतिशत की ढाल पर बनाया जाता है।

संरक्षण नालियां-काली मृदा वाले क्षेत्रों में जहां दरारों के कारण बंध सफल नहीं है, बंधों के विकल्प के रूप में 0.8 मीटर गहराई, 0.6 मीटर आधार चौड़ाई तथा 4.5 मीटर ऊपरी चौड़ाई वाली नालियां बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। ये खेतों में होने वाले अधिकतम अपवाह का भण्डारण करती हे तथा खेत के नीचे की ओर होने वाले क्षरण को रोकती है। इसके अतिरिक्त गड्ढों में भण्डार किया गया पानी सूखे की स्थिति के दिनों में जीवन रक्षा/पूरक सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। ये नालियां 90 प्रतिशत से अधिक वार्षिक अपवाह को समाहित करने की क्षमता रखती हैं जिसको हम पूरक सिंचाई हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं।

सीढ़ीनुमा पट्टियां-सीढ़ीनुमा पट्टियां प्रणाली में समोच्य रेखा के साथ वाले खेतों में ढलान को आधा काटकर तथा आधा भराव करके पट्टियां बनाई जाती है तथा यह प्रणाली 1100 मिलीमीटर वर्षा एवं 10-33 प्रतिशत ढलान वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनाई जा सकती है। हिमालय के 75.8 प्रतिशत तक के तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में इस प्रणाली के अंतर्गत खेती की जा रही है। इन क्षेत्रों में संरक्षित नमी के आधार पर छोटे दानेदार फसलें, दलहन, तिलहन, आलू सब्जियां और गेहूं आदि सफलतापूर्वक उगाये जा सकते हैं। सीढ़ीनुमा पट्टियों से अपवाह व मृदा हानि में क्रमश: 92 प्रतिशत व 96 प्रतिशत की अधिकतम कमी देखी गई है।

समोच्य खाइया-समोच्य खाईया, भूमि ढाल के दोनों ओर निरंतर या बिखरे हुए ढंग से खाई खोदने की पद्धति है। ये ढालू व वन क्षेत्र के लिए उपयोगी है। खाईयां, अपवाह के वेग को समाप्त कर देती है तथा उसके सम्पूर्ण या अधिकतर भाग का भण्डारण करती हैं। रोका गया अपवाह मृदा में निस्सरण द्वारा पौधों के लिए नमी रूप में उपलब्ध रहता है। खाईयां साधारणतया 30-50 सेंटीमीटर, चौड़ी एवं 30-50 सेंटीमीटर ही गहरी होती है। निरंतर खाईयों के मामले में लम्बाई 10-20 सेंटीमीटर के बीच प्रतिबंधित है, जबकि बिखरी हुई खाईयों में यह 2-4 मीटर के बीच रखी गई है। बिखरी हुई खाई पद्धति में खाईयां एक पंक्ति छोड़कर दूसरी में एक के नीचे एक सीधे देखी जा सकती है। खाई पंक्तियों के बीच का स्थान 4-6 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर किस प्रकार के वृक्ष या झाड़ियों का रोपण किया जाना है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में निरंतर खाईयों की सिफारिश की जाती है। जबकि अति वर्षा वाले क्षेत्रों में बिखरी हुई खाई पद्धति अपनाई गई है। खाई पंक्तियों के बीच वाले स्थान को चारा घासों से रोपित किया जाता है।

अत: किसान भाइयों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी जमीन को भौगोलिक स्थिति व वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए जहां तक संभव हो वानस्पतिक विधियों को अपनाते हुए खेती करें। जहां ये विधियां पर्याप्त न हों वहीं पर यांत्रिक विधियों पर कुछ निवेश करके अपनी बहुमूल्य जमीन को बहने से अवश्य रोकें।

अद्भुत वृक्ष

न मानो तो पत्थर और मानो तो पत्थर में भी भगवान वास करते हैं। हमारा देश अद्भुत विचारधाराओं और परम्पराओं का देश है। यहां की संस्कृति में न केवल अद्भुत बातें हैं बल्कि यहां की प्रकृति भी अचम्भित कर देने वाली व नये-नये रंगों में आती है।

हिमाचल की तो बात ही क्या? कण-कण में ईश्वर विश्वास और प्रमाण के लिए यहां के अति प्राचीन मंदिरों में कोई निशान या मूर्तियां। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति रूप में ईश्वर अपनी अजब लीला दिखाते हैं। यहां के पेड़-पौधे भी भगवान के अस्तित्व को स्वीकारते हैं।

चम्बा तहसील के परगना हल में एक गांव है बन्जाह। ये गांव सीला प्राट पंचायत में आता है और सीला प्राट से लगभग सात किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो गांव के लोगों के अनुसार 12वीं शताब्दी का है। यहां माता शीतला और मां काली की पूजा होती है। यानि मंदिर दो देवियों को समर्पित है।

मंदिर के पिछवाड़े में एक वृक्ष है। गांव के लोग जिसे 'बन्नी मां का पेड़' कहते हैं। पेड़ की खास बात ये है कि एक साल इसका एक ओर का आधा भाग हरा रहता है दूसरी ओर का आधा भाग सूख जाता है और दूसरे साल दूसरी तरफ का। गांव में मान्यता है कि यह वृक्ष दोनों देवियों का है। एक साल एक देवी को प्रसन्न रखता है और दूसरे साल दूसरी देवी को। यानि एक वर्ष तक मां काली वाला भाग हरा रहता है तो दूसरे वर्ष शीतला माता का। ऐसी है हमारी संस्कृति और हमारा विश्वास जिसकी जिंदा मिसाल प्रकृति के इन अद्भुत नजारों में भी देखी जा सकती है।

–सीमा परिहार

पहाड़ी भाषा कनै साहित्य लोक मंच

गिरिराज साप्ताहिक शिमला, 26 अगस्त–1 सितम्बर, 2009

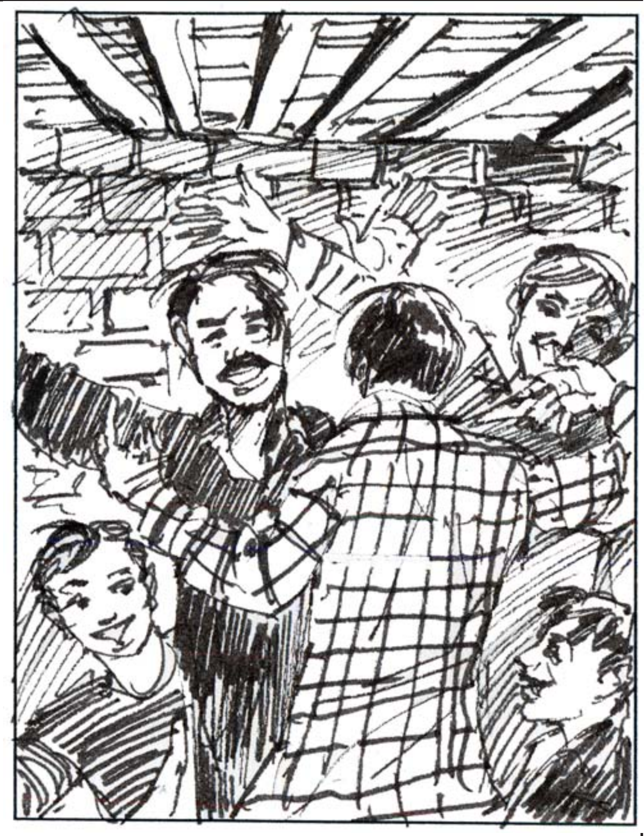

व्यंग

तबेले 'च' इहां बीती रात

● प्रेम पखरोलवी

दिखिया नी तां सुणिया तां हुंगा तबेला तुसां? तबेला...अर्थात घुड़साल...अंदर घोड़े ही घोड़े। तांह पासें घोड़े दा मुंह होर उत्तांह घोड़े दी पूछ! अक्खें बक्खें सैडल, चाबुक घुंघुरूआं आली पेटियां, नुकेल... चारा (घा) पाणे आले हथियार। हां, एही किच्छ दिकखणे मिलदा तबेले री दिवालां पांधे। देहणे बाएं, विच्च विच्च लकड़िया रा किच्छ फट्टे कन्ने निके छुके टुकड़े। दत घाए री... कन्ने सामणे जरा कुदरेंगेडें धुआखियां बलदी लालटैण।

राती जो दस बजदियां ने तबेला डिस्को खुली जाएं। पर भीतरें घोड़ियां ते सिवा होर कोई नी ए! कुतूहं तां एह पंज सितारा छैल होटल, तां कुतूह तिसरे तहखाने 'च' बणी रा एह अंधेखड़ा दिया तबेला। पर एहदे अंदर जाणे री भी मोटी फीस। पर कुस जो परवाह ए फीसा री? कोई कमी नी ए देनदारां री एत्थी। ले आ.. हौलें हौलें भरोई चल्लया तबेला घोड़ेयां ने कोई बचारा कल्ला दुक्कला साथिया री टोहा च तां कोई अपणे हमजोलिए दी सेवा खातिर रसपान च बिज़ी। सामणे मेंजा उप्पर हरे हरे मेजपोश बिछी रे.. .किच्छ किच्छ हरे सफेद रंगा मिलायी ने चैक डिज़ेन बणाइ रो मेंज़ा पांधे, ठीक गब्भैं (सेंटरा च) इक लालटैण जगा दी पर इसा री लो तां बस मेंज़ा पांधे रक्खियां चीज़ा तिक्कर ई पुज्जा कदी... आसें पासें बैठियो लोक तां घणे अंघे निहारे च हन। कोई कोई सिरगिटा दा सूटा खिंजदा तां पता लग्गदा जे एह सारे कुर्सियां पर बैठी रे! एह सब घुड़सवार ही तां हन! हा, लाइटर हण फिरी जगेया... सामणे इक घणियां कालिया मुच्छां आला हट्टा कट्टा छोकरा इक्को छैल छबीलिया छोरिया सौगी...उरी...उरी...उरी...टाप. ..टाप...टाप।

धोखा मत खांदे...एह घोड़े री टाप नी ए एह ऐ तबेले री संगीत लहरी! इहां लग्गदा जियां एह संगीता री 'वाज' तबेले अंदर बसी गइओ। एह 'वाज' हौलें हौंले किच्छ तेज होणा लग दी...एह दिक्खा...ओह सामणे... इक जोड़ा (कप्पल) लगी रा थिरकणा...इक ओह, होर कल्ला छोकर ठुमकदा लग्गी रा.. एह तां बस कल्ला इ मसत रा...बस नच्ची जादा। कोई एसरा संगी साथी नी...देर होई गई हण ता थकोई भी गिया हुंगा... हां, ग्यारह बजणा लग्गी रे...म्यूज़क कदी हौलें, कदी तेज़ तीव्र... कन्ने फलोरा पांधे.... कदी इक्क, कदी दो, कदी कोई भी नी...कैंह जे हुण मते सारे घुड़सवार खाणो पीणो च बिज़ीहन! हां भई माहौल एहड़ा जे पहला पेट पूजा फेरी कम्म दूजा।

सारियां मेज़ा रुकी गइयां...कुत्थी देसी तां कुत्थी विदेशी जोड़े...कुस्सी रे हत्थं च जाम तां कुसी रे मुहें च मुंगफली...तां कोई कोई टेस्टी जाइकेदार पकवानां–डिशां जो खाली करने ताई बड़े व्यस्त। कुछ मिनटां बाद छोकरे कन्ने छोकरियां रा इक्क बड्डा रेला एत्थू सामणे ऐ शायद किच्छ समा अंधेरे च सौगी बिताणे वास्ते एह लोग एत्थू न्याहरे च आए हन... लो (लाइट) नी सूट करा दी एन्हां जो.. .पर एह क्या... किस्मता री गल्ल बुरी ए...एत्थू इनहां जो कोई मेज खाली नी मिला दी... हारी फारी एह दीवाने होरना सौगी एडजस्ट होणे दी फिराक च हन... मौज मस्ती रे बदलें उदासी कन्ने डिसअप्पॉयमेंट सामणे ए।

फ्लोर पर हुंण इक सरदार जी मेमा सौगी थिरका कदे...ब्लैक–व्हाइट 'ट्यूनिक च' इक मुटियार हत्थे हिलाई हिलाई मटकां करदी... इतणे च तिसा रे हत्थे थम्म्णे आला इक जवान औंदा ए– खैर एसरा मटकणा कम्मे आया। जां आं आं ऊं ऊं टपटप टप!

एह संगीत कुस्सी री समझे ते बाहर ए। कई रूप रंग हन... युवक–युवतियां सब अपणा अपणा रूप रंग कन्ने ढंग (नखरा) दस्सा करदे, म्यूज़क...कन्ने डांस एह नज्जारा ए तबेले च। मते सारे तालियां ई बजाई जा दे... कुसी री सफेद पैंअ लिशका दी तां कुसी री लाल कमीज़... कोई साड़ी वाली सुंदरी ए तां कोई स्कर्ट आली मेम! सारे ई अपणे अपणे च मस्त, व्यस्त–दीन दुनिया ते बेखबर। कुछ अपणे अपणे साथी कन्ने...कन्ने कितणे सारे एत्थु भी किल्ले। दिखदियां सुणदियां मसियां खरमत्तिया करदियां बारह बजी जांदे–कई तां थक्की हारी भुयां पैइ जांदे–सौई जांदे– किच्छ लोग खाखा लगदे–बस जरा देर शांति लगदी–कन्ने फिरी महफल गर्म–बड़े जोरा दा धमाका ...आना जाई शुरू लोग डेढ़ दो बजे ताई भी रुकदे...अपणी ता हिम्मत जवाब देया थी करदी–वाडली सुणोआ। गेट बंद होई जाणा सोचिया. ..चल मना.. तबेले च क्या सौणा... एह भी कोई ढंग ए...आखिर असां बाहर आई गए–जितणे नौहते उतणा पुन्न.. .पता नी तबेले दी बलाई ते कियां करी बची ने आई गए–शुक्राना एही जे जान बची लक्खा पाए–लुटोंदे लुटोंदे घरां जो आए। ●

कबता

धारां

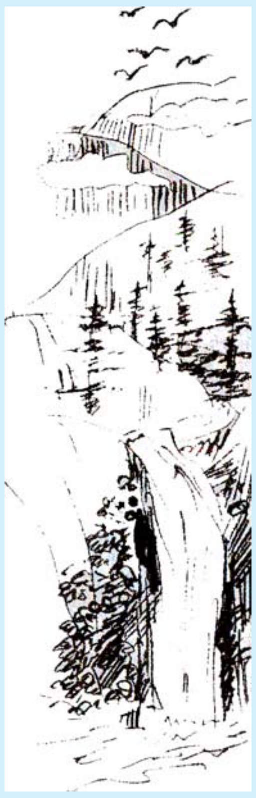

अम्बर छून्दियां लगदियां धारां।
मौसम–मौसम सजदियां धारां।।

हवा बसन्ती गित्तलु लान्दी।
खिड़–खिड़, खिड़–खिड़ हसदियां धारां।।

मौसम–मौसम बदली नुहारां।
जिन्दगी दा सच्च दस्सदियां धारां।।

झर–झर, झर–झर, बगदे झरणे।
घर–घर खुशियां बंडदियां धारां।।

रंग–बिरंगे पंच्छी उड्डदे।
चुरभुर–चुरभुर करदियां धारां।।

धुप्प–धूरी कन्ने बहल–बरखा।
दिले ने लाई रक्खदियां धारां।।

लम्मियां हेक्कां गीत सुणी ने।
बौंसरिया पुर नच्चदियां धारां।।

जगह–जगह मन्दर देवतेयां दे।
सच्चियां–सुच्चियां लगदियां धारां।।

● अशोक 'दर्द'

हासे मखोले दी गल्ल

जुग–जुग जीये साडा चौकीदार

● कमलेश कुमारी

अधिया राती दा टैम था। इक ग्राएं च इक बूढ़ा चौकीदार रोज ग्राएं दा पेहरा दिन्दा था। ग्रांए दे सारे माणु बेफिकर होई कनै सौंदे थे। इक बरी क्या होया कि इक बुढ़ीया अम्मां री बकरी राती अम्बे दे ढक्के बार बनियों रई गई। तां सै बकरी नेरे च लगीयो खरडैयाणा। चौकीदारे दिखैया कि अम्बे हेठ कोई माणु है। सै राती कया करां दा है? जिया ही चौकीदार अम्बे हठ गया तां घुंघरूआं दी छण–मण सुणी कनै सै समझी गया कि बुढ़ीया री बकरी है। बकरी कैली डरा दी है। बूढ़ा चौकीदार भी बसौणे ताई बकरीया सामणे बैठी गया। तीनी बीड़ी लगाई लेई। कनै बकरीया ने लगैया गलाणां डरदी मत मै भी तेरीया सौगी हेया।

जाली चौकीदारे तीली जलाई तां च्ंिग तिसरिया धोतीया पर पेई गई। तीनी ख्याल ही नहीं किता कनै सै फेरी बकरीया ने लगैया गलाणां। डरदी मत मैं तेरीया सौगी हेया। असे दोआ जणयो अज ग्राएं दी चौकीदारी करणी। कनै बूढ़ा बीड़ी भी पिन्दा रैहा। जाली जे तिसजो लते सेक लगेया, तां सैल गेया रडाणां। बचाई लेआ वो लोकों, बचाई लेआ वो लोकों।

भला लोक किती सुणन। तिना जो निंद्रा च जागदे रेंहा वो लोकों–जागदे रेंहा वो लोकों ही सुणाई देआ करदा था।

लोक तां अनी सुणा दे थे पर सौगी जेड़ी बकरी अम्बे हेठ बनियों थी। सै चौकीदारा जो जणदा देखी कनै घबराई गई। कनै तिसे ताली दम तोड़ी दिता। भ्यागा बुढ़ी अपणीया बकरीया दूणा आई। तां कया दिखे बकरी तां मरी पेईयो कनै बूढ़ा चौकीदार भी लक्के ते लेई कनै पेरां तक फकोया पेया सै इस हादसे देखी कनै जोरा–जोरा कनै लगी रोणा। मेरीया बकरीया बचाई लैआ, मेरीया बकरीया बचाई लेआ। भ्यागा–भ्यागा ही शोर सुणी कनै देखदेयां–देखदेयां सारा ग्रां किट्ठा होई गया। बुढ़ी अम्मा मच्छीया साई तड़फे। मेरी बकरी दूध देआं थी। इसा रा दूध बेची कनै ही मैं अपणा गुजारा करां थी। हुण तां मैं भुखिया मरी जाणा। सारे माणु अम्मा जो दम दलासा देणा लगे। कई चुप कराणा लगे। ग्राएं दा इक माण बोलदा अम्मा चुप होई जा, डंगरे दे डाक्टरे लैओंणे भेजे हन तेरीया बकरीया राजी होई जाणा। इतने च दूआ माणु बोलदा बकरी तां लगदा मरी गई होणी पर चौकीदारा ताई दिखा इस जो कया होया। किन्ना फकोया। इसदी दवा–दारू करां। फेरी इक होर छोरू माणुये दे डाक्टरे लैओणे ताई भेजेया।

दोआ डाक्टर घटना स्थानां ते पुजी गए। डंगरे दे डाक्टरे बकरीया जो हत्थ लाई कनै दिखैया तां सै ठण्डी होई गईयो थी। दूजे पासे चौकीदारा जो भी माणुये रा डाक्टर दिखणा लगेंया। चौकीदारा री लक्कमे ते लेई कनै पैरा तक बुरी हालत है सै तां फकोई गया है।

इतने च फेरी बुढ़ीये अम्मे रोणे–पटोणे जो जोर देई दित्ता। जे मेरी बकरी ठीक नहीं होई तां मैं भी मरी जाणा। दूजे पासे लोक चौकीदारा जो ठीक होणे री चिनता च फंसेयो थे। हुण नवां चौकीदार कुतीते लैओंगे।

फेरी दोआ डाक्टर इक पासे होई कनै आपी बिचाईये सलाह करना लगे। तिना दोआ डाक्टर सारे ग्राए दे माणु किट्ठा कित्ते कनै तिना जो दसणा लगे।

सुणा ग्राएं देआ लोको असां दोआ डाक्टरां जो इक सलाह सुजी है। जे तुसां साडी गल्ल मने जाण तां तुसा रा चौकीदार भी ठीक होई सकदा कनैं अम्मां री बकरी भी दूध देई सकदी है। ग्राए दे माणु बड़े भारी खुशी होये कि असां जो छोड़–छोड़ सलाह दसी देआ। फेरी डंगरे दा डाक्टर ग्राएं देआ लोकां जो लगेया समझाणा। तुसां लोकां जो साडीया इसा सलाह दे दो फायदे होणे।

देखा भाईयो बकरी तां गई मरी, सै दूध देआ थी। अम्मां रा रोजगार चलेया था। दूजे पासे चौकीदार दी धोतीया अग्ग लगी गई। कनै सै लक्के ते लेई कनै पैरा तक फकोई गया। पर लक्के ते ऊपरला हिस्सा ठीक है। असे बकरीया दा पिछला हिस्सा कटी कनै चौकीदारा दे पेटा थले लगाई देणा। अम्मा जो दूध भी मिलदा रैहणा। कनै ग्राएं दी चौकीदारी भी हुन्दी रैहणी। इसा सलाह ते अम्मां कनै ग्राएं दे लोक बड़े भारी खुशी होये। कनैं सारे गलाणा लगे जुग–जुग जीये साडा चौकीदार।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर रैली को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

'सौर नगर' स्थापित करने के प्रयास किए ...

(पृष्ठ एक का शेष) स्थानीय लोगों के हितों को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रो. धूमल ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण को बल दें तथा पर्यावरण विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाएं, ताकि विश्व भर के लोग हिमाचल प्रदेश आकर प्रदेश के सौम्य पर्यावरण का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिमाचली का यह कर्त्तव्य है कि वे प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखें। इस अवसर पर उन्होंने 'हरित प्रेरणा' पत्रिका का विमोचन भी किया।

सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं हिम ऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजय भण्डारी ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी, मुख्य संसदीय सचिव श्री सतपाल सिंह सत्ती, विधायक श्री सुरेश भारद्वाज एवं किशोरी लाल सागर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित

बाद में, मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने राजीव चौक छोटा शिमला में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। शिक्षा मंत्री श्री आई.डी. धीमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी कांग्रेस विधायक दल की नेता श्रीमती विद्या स्टोक्स, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री कौल सिंह ठाकुर, विधायक श्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला के महापौर श्री नरेन्द्र कटारिया तथा नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

सिरमौर जिले के मुख्यालय में उपायुक्त श्री पदम सिंह चौहान ने जानकारी दी कि ज़िला सिरमौर में ऊर्जा विभाग ने अक्षय ऊर्जा तथा ईंधन कार्यकुशल साधनों के वितरण एवं निष्पादन में विभिन्न सार्थक उपलब्धियां हासिल की है।

उन्होंने कहा कि ज़िला में अब तक 367 सौलर स्ट्रीट लाईटें, 477 सौर घरेलु लाईटें, 1130 सोलर कुकर, पानी गर्म करने के लिए 61 सौर जल तापीय संयंत्र, लघु सिंचाई योजना के लिए 15 हाइड्रेम, 3817 पोटेबल धुंआ रहित चुल्हों के अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को 5033 प्रैशर कुकर, 609 सीएफएल, 1093 स्टोव विशेष अनुदान पर चिन्हित परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ज़िला में लघु विद्युत् की 48 मैगावाट की क्षमता है जिसमें से चांदनी व मानल विद्युत् परियोजनाओं में 6 मैगावाट का उत्पादन निजी क्षेत्र के सहयोग से शुरू हो चुका है एवं पालर–1 व टिम्बी में 6 मैगावाट का विद्युत् उत्पादन इस वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 22 अन्य लघु जल विद्युत् परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू हो गया है।

मंडी जिले में 115 करोड़ के ऋण वितरित

चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जिला के बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 114 करोड़ 30 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त श्री रितेश चौहान ने गत दिनों मंडी में बैंकों की जिला सलाहकार समिति एवं जिला समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि 90 करोड़ 79 लाख रुपये प्राथमिकता क्षेत्र व 23 करोड़ 51 लाख रुपये गैर प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में 32 करोड़ 54 लाख, सेवा व लघु उद्योग क्षेत्र में 23 करोड़ 91 लाख रुपए तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 34 करोड़ 34 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए।

श्री रितेश चौहान ने बैंकर्ज, सरकारी विभागों व विकास एजैंसियों का आह्वान किया कि चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को विशेष कर स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक वितपोषण करें ताकि जिला में स्वरोजगार के अधिक– से–अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें।

एक परोपकारी कार्य

जल प्रदूषण की समस्या से आज सम्पूर्ण विश्व ही जूझ रहा है। मण्डी जिले के करसोग उपमण्डल के गांव पांगणा के मध्य से गुजरने वाली खड्ड के विशाल जल कुंड (आल) में जून मास के अंतिम सप्ताह में प्रदूषण के कारण हजारों मछलियां मर गईं। प्रशासन द्वारा इस जल की पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में जांच करवाई गई। गांव के युवा धर्मपाल गुप्ता, मेहर सिंह ठाकुर, मुकेश गुप्ता, धर्मेन्द्र, विजय, तेजराम गौतम, वेद प्रकाश, डॉ जगदीश आदि ने इस जलकुंड में मरी मछलियों को निकालने व प्रदूषित जल को गांव के लोगों को साथ लेकर साफ करने का निर्णय लिया। लगभग अढ़ाई सौ फुट घेरे व लगभग 15 फुट गहरी इस आल के दूषित पानी को निकाल कर इसे प्रदूषण मुक्त करने का काम इतना आसान नहीं था। इस कार्य में पांगणा गांव के महिला, पुरुष, युवा, बच्चे व बूढ़े सभी ने सहयोग दिया।

इस जलकुंड को प्रदूषण मुक्त कर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस पावन कुंड को प्रदूषण मुक्त करना यकीनन एक ऐसा साकार स्वप्न है जिसके बारे में कल तक कोई सोच भी नहीं सकता था। निस्संदेह जन सहभागिता से इस कार्य को पूर्ण देख एक चीनी कहावत सत्य साबित हुई कि हजार मील का लंबा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है।

● डॉ. जगदीश कुमार शर्मा

हिमालय की गोद में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान

(पृष्ठ एक का शेष) आयात किया गया है। तथा इस पर चार करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। हाल ही में हालैंड से आए एक दल ने इस मैदान की गहन जांच कर इसे अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सही पाया है। वे शीघ्र ही इस बारे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एस्ट्रोटर्फ के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। इसके लिए 80 हजार लीटर क्षमता वाला भण्डारण टैंक बनाया गया है। इस क्षेत्र में सर्दियों में अधिक ठंड रहती है तथा सम्पूर्ण घाटी बर्फ से ढक जाती है। लेकिन यहां स्थापित अत्याधुनिक एस्ट्रोटर्फ में शून्य से कम तापमान को सहने की क्षमता है। तथा ऐसे तापमान को खेल प्रशिक्षण के लिए बेहतर आंका गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शिलारू में वर्ष 1986 में खेल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। यहां अप्रैल माह से लेकर सितम्बर माह तक विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किए जाते हैं। संस्थान में बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, कुश्ती, वालीबॉल, बैडमिंटन के प्रशिक्षण के लिए दो बड़े इनडोर स्टेडियम हैं। विगत वर्ष चीन में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में रजत पदक जीतने वाले श्री बजिन्द्र सिंह व कुश्ती में कांस्य पदक हासिल करने वाले श्री सुशील कुमार ने भी यहां रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये दोनों खिलाड़ी यहां अनेक बार प्रशिक्षण कैम्प में हिस्सा ले चुके हैं। इस संस्थान में साइक्लिंग के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा यह प्रशिक्षण हिन्दोस्तान तिब्बत मार्ग पर खिलाड़ियों द्वारा ऊंचाई पर साइकिल चलाकर किया जाता है ताकि उनमें शारीरिक क्षमता को बढ़ावा मिल सके।

आजकल इस संस्थान को वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रकुल खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहां वालीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी के लिए सुविधाओं का विशेष विस्तार हो रहा है।

इनडोर स्टेडियम में लकड़ी का नया फर्श लगाने पर 90 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। खिलाड़ियों के रहने के लिए छात्रावास का पुनर्निर्माण अंतिम चरण में है, जहां 90 पुरुष व 50 महिला खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था है। खिलाड़ियों के व्यायाम के लिए अत्याधुनिक उपकरण वाले जिम यहां उपलब्ध हैं। भाप से नहाने की व्यवस्था वाला एक कक्ष भी है। इस अत्याधुनिक एस्ट्रोटर्फ वाले हॉकी मैदान के बन जाने से प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक नई आशा की किरण जगी है।

यह मैदान प्रदेश के उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि अभी उन्हें घास के मैदान पर ही प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है। यह मैदान हिमाचल में सोलन जिले के चायल में 7500 फुट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचाई वाले क्रिकेट मैदान के बाद दूसरा है।

प्रदेश सरकार भी राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी के अंतर्गत बिलासपुर, हमीरपुर तथा धर्मशाला में एथलेटिक्स व हॉकी के लिए ट्रैक व एस्ट्रोटर्फ वाले मैदान निर्मित किए जा रहे हैं।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL THEOG DISTT. SHIMLA (H.P.)

Tender Notice

Sealed item rate tenders are hereby invited from registered contractors of appropriate class enlisted with HPPWD/CPWD and I&PH on prescribed tender from MW-4 and MW-7. Obtainable from office of Executive Officer, Municipal Council, Theog, Distt. Shimla, HP. on the cash payment mentioned below. The tender will be received in office of undersigned on or before 07.09.2009 at 11.30 AM. The tender will be opened on the same day and date at 2.30 PM in the presence of contractors or their authorized representative who may wish to attend the same. The tender form will be sold on or before 05.09.2009 (4.00 PM). **Work No. 1**:- C/O Community Hall at Theog Near DAV School (SH: Site Development Damage Portation due to heavy rain fall). **Estimated Cost**:- Rs 508735/-, **Earnest money**:- 10175/-, **Time limit**:- 90 days, **Cost of form**:- Rs. 300/-.

TERMS & CONDITIONS:- 1. Conditional and telegraphically/ fax/with out earnest money and on with out prescribed tender form will be rejected straight way. 2. Tender Documents will be issued to only those contractor who have executed the work of rupees five lac at least in last one year. 3. Earnest money will be deposited in the shape o currency note/local bank draft along with tender form. 4. The Municipal Council theog reserves the tight to reject/accept any or all the tenders. 5. The validity of tender will be 90 days from the date of opening the tenders. 6. Sale tax no. from the concerned authority be produced the undersigned at the time of sale of tender. 7. The rates should be quoted in words as well as figures.

Sd./- Executive Officer
Municipal Council
Theog, Distt. Shimla (HP).

No. MCT/2009/-333 Dated:- 20-08-09

HP PWD CORRIGENDUM

The tender invite by the Executive Engineer Jubbal Division, HP PWD Jubbal vide letter No. PW-JD-E-Tender/2008-4441-43, dated 22.7.2009 and even No. JD-E-Tender/2008-4547-49 dated 24.7.2009 appeared in Giriraj Weekly in its edition 12 to 18th August, 2009 and 5 to 11 August, 2009 vide release order No. 1056/09-10 and 1004/09-10 are hereby postponed due to technical reasons and now will be received/opened on 31.8.2009 at 10.30 AM/11 AM. The tender documents now be had from this office on 29.8.2009 upto 4.00 PM. Other terms and conditions of the tender shall remain unchanged.

1294/09-10 Him Suchna avam Jan Sampark

सूचना, शिक्षा सम्प्रेषण गतिविधियां...

(पृष्ठ एक का शेष)जिला स्तरीय शिविरों में अन्य गतिविधियों के साथ–साथ स्व–सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बिक्री एवं प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिविर के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को 25 हजार रुपये, परियोजना स्तरीय शिविर के लिए 10 हजार रुपये, पर्यवेक्षक वृत्त स्तरीय शिविरों के लिए 2 हजार रुपये तथा आंगनबाड़ी स्तरीय शिविर के लिए 500 रुपये की राशि जारी की गयी है।

श्रीमती चौधरी ने कहा कि इस वर्ष आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 'लैक्सी फंड' के तहत 1000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस राशि को आपातकालीन स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।

प्रदेश को 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम'...

(पृष्ठ एक का शेष) पर्यावरण संरक्षण तथा 'कार्बन न्यूट्रलिटी' प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों, इको क्लबों तथा पंचायतों के सहयोग से लोगों को जागरुक करने के लिए कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां भवनों में वर्षा जल संग्रहण प्रक्रिया को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सौरग्राही तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए।

वन मंत्री ने केन्द्र से आग्रह किया कि वे जलवायु परिवर्तन का वनों तथा हरित आवरण पर प्रभाव के अध्ययन के लिए एक नयी केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ करने का आग्रह किया, जो मैदानी प्रदेशों के वॉटरशैड के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नयी योजना के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कैम्पा अर्थारिटी को अधिसूचित किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया, ताकि इसका कार्य दिसम्बर माह के अंत तक पूरा किया जा सके। उन्होंने केन्द्र सरकार से कैम्पा फंड के अंतर्गत प्रदेश को मूलधन पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज देने का आग्रह किया।

वन मंत्री ने राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के युक्तिकरण को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया तथा कहा कि प्रदेश सरकार ने रंजीत सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है तथा इस संबंध में मंत्रालय को सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाउस गैस रिसाव को कम करने के लिए राज्य स्तरीय 'गवर्निंग काउंसिल' तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उद्‌देश्यों तथा उपलब्धियों के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय 'स्टीयरिंग' समिति का गठन किया है।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की 65वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।

जल विद्युत क्षमता के दोहन में हिमाचल उत्तराखण्ड को सहयोग देगा–मुख्य मंत्री

252 मेगावॉट देबसेरी, 60 मेगावॉट नैटवाड़ मोरी तथा 35 मेगावॉट उत्यासर जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करेगा सतलुज जल विद्युत निगम

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकारों द्वारा उपलब्ध जलविद्युत क्षमता के दोहन तथा परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर निकट समन्वय से कार्य किया जाएगा, ताकि दोनों राज्यों के हितों को सुनिश्चित बनाया जा सके। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में उत्तराखंड के मुख्य मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल के साथ आयोजित बैठक में दी। प्रो. धूमल ने कहा कि दोनों प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं तथा दोनों प्रदेशों में अपार जलविद्युत क्षमता विद्यमान है।

उन्होंने कहा कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश की सबसे बड़ी 1500 मेगावॉट क्षमता की नाथपा–झाकड़ी जल विद्युत परियोजना का निष्पादन सफलतापूर्वक किया गया है, जो देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जलविद्युत क्षमता के दोहन को सुनिश्चित बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य को हर संभव सहयोग देगा।

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड उत्तराखंड में 3 जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करेगी तथा उत्तराखंड में जल विद्युत क्षमता के दोहन में भागीदार बनेगी।

उत्तराखंड में 252 मेगावॉट देबसेरी, 60 मेगावॉट नैटवाड़ मोरी तथा 35 मेगावॉट उत्यासर जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादन के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को आबंटित किया गया है तथा इस पर निकट भविष्य में कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने कहा कि उनकी सरकार जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में संयुक्त उपक्रम में प्रवेश की इच्छुक है, ताकि उपलब्ध जलविद्युत क्षमता का समुचित दोहन सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहभागी बनने का इच्छुक है। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में निष्पादित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं पर दी गई प्रस्तुति में गहरी रुचि ली।

दोनों मुख्य मंत्रियों ने परस्पर हितों के विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबन्ध निदेशक श्री एच.के. शर्मा ने देश तथा देश के बाहर संगठन की गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

सांसद श्री अनुराग ठाकुर तथा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारी आईएएस में शामिल

केन्द्रीय कार्मिक, जन शिकायत एवं पैंशन मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सर्वश्री शेखर गुप्ता, मोहन चौहान, आर.एस. गुप्ता, राजेन्द्र सिंह, अमर सिंह राठौर, पदम सिंह चौहान, अरुण कुमार शर्मा, बी.एम. नैंटा तथा पी.एस. डैक को भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल कर, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिमाचल कॉडर आवंटित किया है।

नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए जन सहयोग की अपील

विद्यालयों व सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जायेगी

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सदन में कहा कि समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। मुख्य मंत्री विपक्ष की नेता श्रीमती विद्या स्टोक्स द्वारा युवा पीढ़ी में नशीले पदार्थों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए लाये गये एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि नशे की प्रवृत्ति के बढ़ने का सबसे अधिक असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की खेती को रोकने के लिए भी कड़े दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग दें। उन्होंने कहा कि पुलिस शैक्षणिक संस्थानों के आसपास व सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ायेगी।

मुख्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2008 में नशे के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में कुल 274 मामले दर्ज किये गये तथा 30 जून तक 197 मामलों में केस दर्ज किये गये। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी।

राज्य में 3582 प्राथमिक सहायक अध्यापक कार्यरत

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक सहायक अध्यापकों को नियमित करने पर विचार करेगी। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों सदन में प्रश्नकाल के दौरान दी।

प्राथमिक सहायक अध्यापकों के नियमितिकरण को लेकर विधायक श्री सुरेश भारद्वाज के प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री ने कहा कि विद्या उपासकों की नियुक्ति भाजपा के समय हुई है तथा सरकार ने इन्हें पांच साल तक हर दो माह में संक्षिप्त (कॅन्डेन्स) कोर्स करवाने के नियम बनाये थे तथा इसके उपरांत उनको नियमितिकरण किये जाने के नियम भी बनाये गये।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने सदन को बताया कि राज्य में 3582 प्राथमिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक सहायक अध्यापक प्रशिक्षित हैं या जिन्होंने पांच वर्ष का लगातार सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, को 4000 रुपये व अन्य को 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

निजी बस ड्राइविंग स्कूल खोला जायेगा

राज्य में निजी बस हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार व परिवहन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। यह वक्तव्य परिवहन मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ने विधान सभा में देते हुए बताया कि हाल ही में चम्बा में हुए बस हादसे का संज्ञान सरकार ने लिया है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग लाइसेंस जांच के लिए विशेष अभियान आरम्भ करेगा। उन्होंने कहा कि जो वाहन चालक, चलती गाड़ी में मोबाइल का प्रयोग करता हुआ पाया जायेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी ड्राइविंग स्कूलों को अनुमति देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा जल्द ही कड़े दिशा निर्देश तैयार किये जायेंगे ताकि लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित बनाई जा सके।

स्वास्थ्य बीमा योजना में एपीएल परिवार शामिल करना विचाराधीन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिंदल ने सदन को बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना में एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवारों को भी शामिल किया जायेगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री, विधायक श्री विपिन सिंह परमार तथा डॉ. राजीव सैजल के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है, जिसने मात्र दो जिलों शिमला व कांगड़ा में इतने अधिक परिवारों को बीमा योजना से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश में 2 लाख 98 हजार बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे। अब तक 80 हजार 242 परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस योजना के तहत 4 करोड़ 21 लाख 66 हजार 288 रुपये का प्रावधान किया गया है।

पुलिस ढांचा सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय मदद का आग्रह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय मदद की मांग की है।

वन मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने गत दिनों दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की ओर से राज्य में गुप्तचर नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जा रहे सुरक्षा सम्बन्धी खर्चे की पूर्ण राशि को राज्य को प्रदान करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मद्द पर वार्षिक 12 करोड़ रुपए खर्च कर रही है जबकि केन्द्र सरकार राज्य को वार्षिक मात्र 2.80 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है।

श्री जे.पी. नड्डा ने राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 46 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस समय गृह मंत्रालय पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मात्र 10 करोड़ रुपए वार्षिक मदद प्रदान कर रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार को तीन आई.आर.बी. बटालियनें स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए इनकी लागत राशि 90:10 के अनुपात में स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस समय

आंतरिक सुरक्षा पर नई दिल्ली में बैठक आयोजित

केन्द्र सरकार पहले वर्ष की निर्माण लागत की 50 प्रतिशत धनराशि प्रदान करती है तथा उन्होंने 50 प्रतिशत निर्माण लागत को पूरे पांच वर्ष तक प्रदान करने का अनुरोध किया क्योंकि पहले पांच सालों के दौरान इनकी ढांचागत निर्माण लागत काफी ज्यादा रहती है। श्री नड्डा ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य में नए औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर विचार कर रही है। उन्होंने इस नए बल के गठन के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग की।

वन मंत्री ने बताया कि राज्य की 1100 किलोमीटर सीमा पड़ोसी राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के साथ लगती है जबकि 200 किलोमीटर क्षेत्र चीन की सीमा से सटा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले दो दशकों से अन्तर्राज्य सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में जुटी है तथा इसके सार्थक परिणाम मिले हैं।

श्री नड्डा ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों एवं रेंज स्तर पर 'क्विक रिसपांस टीम तथा स्पैशल इंटरवैन्शन इकाईयों' को तैनात किया गया है तथा किसी भी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए गुप्तचर विभाग में विशेष कार्य समूहों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में धर्मशाला एवं शिमला में विशेष कार्य समूह की एक इकाई की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि आतंकवाद विरोधी दस्ते की तर्ज पर गुप्तचर विभाग में इंटैलीजैंस तथा ऑप्रेशन पर आधारित स्पैशल सैल गठित किए गए हैं।

वन मंत्री ने बताया कि राज्य में आर्थिक अपराधों तथा भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए पुलिस महानिदेशक स्तर पर एक अलग विजिलैंस एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो सालों के दौरान राज्य में 15 नए पुलिस थानों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक स्टेशन में महिला आरक्षी की तैनाती की गई हैं। उन्होंने बताया कि इन पुलिस थानों में गतिशीलता एवं संचार व्यवस्था बनाए रखने के विशेष प्रबन्ध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है तथा व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध किए गए हैं।

प्रकाशकः बी.डी. शर्मा, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हि.प्र. शिमला–171002, मुद्रकः राजीव कुमार शंकर, नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला–171005, फोनः 2830378, प्रधान सम्पादकः बी.डी. शर्मा, वरिष्ठ सम्पादकः आर.एस. नेगी, सम्पादकः यादविन्दर सिंह चौहान, कार्यालयः हि.प्र. मुद्रणालय परिसर, शिमला–171005, फोन व फैक्सः 2633145, ई–मेलः girirajhp@gmail.com., girirajhp@yahoo.co.in OR girirajweekly 1978 @yahoo.co.in प्राप्ति स्थानः गिरिराज कार्यालय। (गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं)